Seventeenth Loksabha

an>

DISCUSSION UNDER RULE 193

Need to promote sports in India and steps taken by the Government in this regard

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अब आइटम नंबर 18 को ले लिया जाए, क्योंकि खेल एक महत्वपूर्ण विषय है। आज इस पर चर्चा हो जाए और कल माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे।

HON. CHAIRPERSON: Does the House agree to it?

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Okay. Item No. 18, Discussion under Rule 193 to continue.

Shri Gopal Shetty -- not present.

Shri B. Manickam Tagore

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Thank you, Chairman Sir, for continuing the discussion on the promotion of sports under Rule 193. I would have liked to say about the Cabinet Minister, but the young MoS is sitting here to hear our views.

Sports unites youth, sports gives confidence, and sports builds trust in communities. The need for Bharat Jodo is an important process, and with Bharat Jodo only Bharat Jeeto can happen. How many districts have world-class infrastructure? Can we develop infrastructure in district-specific talents? Can amenities be developed in each district accordingly?

There is a story of a young under-20 athlete from Madurai whose name is Selva Prabhu. He has won an under-20 medal in triple-jump, and the Government of Tamil Nadu -- under the hon. Chief Minister -- has given Rs. 4 lakh as cash award for him. But what is the help from the Central Government? How are we going to use that talent to make him play for India in the future? Under-20 is an age where we need to invest a lot, and a budding talent can be developed as a player for India in the next Olympics.

Now, the youth is getting attracted and involved in many sports other than cricket.

15.00hrs

Federations and associations play a major role in sports. Private sector also plays a very important role in the investment part of sports. How is the Ministry planning to welcome the private sector to support rural sports in the southern part and other parts of India. How are the private companies going to be encouraged to support rural people?

We have a tax terrorism mentality now. All the agencies are now after the business people who are not supporting the Government. Will there be a change in this mindset and will they be encouraged to support the private sector to support the major rural sports events? Will there be any concessions given to them?

Further, sensitivity of the federations is needed. So, we need to develop sensitivity for the people in the federations. We hear about many incidents of insensitive attitude of the federations. How does the Sports Ministry appreciate the sensitivity of an association? At the same time, how does it punish or how does it handle the insensitivity of the associations?

Women cricket team and women hockey team have different challenges. As a society, how do we support those sisters who played an important role in making India proud at the world forums? These women teams, particularly the women cricket team and hockey team, and the women players need to be appreciated and their talents should be showcased and celebrated.

In the reply to a Question asked in the Lok Sabha, the hon. Sports Minister replied that under the Khelo India Scheme, there are 300 projects sanctioned and around Rs. 2753.78 crores have been spent. It is well appreciated that the Government is taking interest in investing in the projects. But there are only five projects announced for Tamil Nadu out of 300 projects. Why is this discrimination? Tamil Nadu also needs support from the Central Government. I hope in the coming year, Tamil Nadu will also be given its due share in promotion of sports.

Our Chief Minister of Tamil Nadu has announced to make a sports city. Will the Central Government support the sports city plan of the State Government? Will the Modi Sarkar stop the discrimination against Tamil Nadu and support Tamil Nadu in this field?

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के तहत खेल के विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद । इस विषय पर पहले भी चर्चा हुई थी और आज वापस चर्चा हो रही है ।

भारत खेल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण देश रहा है। हमारे देश के युवा स्वाभाविक रूप से खेल में रुचि रखते हैं। कुछ समय पहले तक भारत मात्र एक खेल के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में हमारे देश में माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'खेलो इंडिया' के रूप में खेल को एक नया रूप देने का प्रयास किया है। 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम भारत में खेल विकास के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना है। इसे पहली बार वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। यह कार्यक्रम भारत की खेल संस्कृतियों को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने संशोधित खेलो इंडिया के क्रियान्वयन को मंजूरी दी थी, जिसे पहले राजीव गांधी खेल अभियान के नाम से जाना जाता था। यह अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम और नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च सिस्टम प्रोग्राम को जोड़ता है।

सभापति जी, इस योजना का प्रमुख लक्ष्य एथलीटों को उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना और उन्हें आगे वित्तीय सहायता के लिए पहचानना है। इसके अतिरिक्त बजट, 2022 में 'खेलो इंडिया' के लिए आवंटन में 48 प्रतिशत वृद्धि हुई। हालांकि यह देखना बाकी है कि जमीनी स्तर पर इस कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाए। युवा भागीदारी में बहुत वृद्धि हुई है। भारत में ओलम्पिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारी भागादारी में जो बाधा आती थी, जब से 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम वर्ष 2018 में शुरू हुआ है, तब से इंडिया स्कूल गेम्स में वर्ष 2018 में 3764 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इसके बाद दो वर्षों में पूरे देश में एथलीट्स की संख्या 6000 तक पहुंच गई है। पूरे देश में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 7 राज्यों में 143 'खेलो इंडिया' जिला केन्द्र बनाए गए। इस परियोजना का कुल बजट 14 करोड़ से अधिक है। इस परियोजना में युवा एथलीटों को उनके चुने हुए खेलों में उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करने को प्राथमिकता दी गई है।

सभापति जी, ओलम्पिक और पैरा-ओलम्पिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सितम्बर, 2014 में 'टारगेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम' शुरू की गई, जिसे अप्रैल, 2018 में 'टॉप्स' एथलीटों को प्रबंधित करने और व्यापक समर्थन प्रदान करने के लिए एक तकनीकी सहायता टीम बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। यह योजना पूरी तरह से चालू है और वर्ष 2020 के ओलम्पिक और पैरा-ओलम्पिक खेलों के लिए पहचाने जाने वाले सम्भावित एथलीटों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है, जैसे विदेशी प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता उपकरण और कोचिंग शिविर लगाना और साथ ही 50 हजार रुपये का मासिक वजीफा प्रत्येक एथलीट को प्रदान किया जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुसार यह योजना वर्तमान में 13 खेल विषयों में 104 टॉप्स कोर ग्रुप एथलीटों का समर्थन करती है।

सरकार खेलों और खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए 'एक राज्य, एक खेल' नीति लागू करने की योजना बना रही है, जिसका हाल ही में केन्द्रीय खेल राज्य मंत्री माननीय प्रामाणिक जी ने महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत किया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में खेलों को महत्व देने के लिए, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे ग्रामीण खेल हैं, जैसे पिछले दिनों में कबड्डी को महत्व दिया गया। कुश्ती में आप देखेंगे कि कुश्ती में हमारी बहनों-बेटियों ने जिस प्रकार का परचम लहराया है, सामान्य परिवारों की बेटियां किस प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में आई हैं। इसी प्रकार से एथलेटिक्स में आप देखेंगे कि हमारे बच्चों ने पूरी दुनिया में परचम लहराया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय खेल राज्य मंत्री प्रामाणिक जी यहां बैठे हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि ग्रामीण अंचल में खेलों को विशेष महत्व देना चाहिए। अगर हम गांवों में छोटे-छोटे बच्चों को प्रोत्साहन देंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा नर्सरी विंग्स खुलेंगी, स्कूलों से बच्चों को सेलेक्ट करके नर्सरी विंग खोलकर, यदि हम उनको छात्रवृत्ति भी देंगे तो उससे हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों को अवसर मिलेगा और मौका मिलने के बाद जब वे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर उनका प्रभाव पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंदर बावड़ी गांव के अंदर बालिकाओं की एक एकैडेमी चलती है। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि आप उसे 'खेलो इंडिया' में परिवर्तित कर लेंगे तो छोटी-छोटी बालिकाएं आगे बढ़ सकेंगी। कबड्डी में भी हमारा एक छोटा सा गांव है, वहां की अंडर-18 की बेटियों ने राष्ट्रीय लेवल पर दो बार लगातार खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।

माननीय सभापति जी, मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से हूं और मैं जिस गांव में रहता हूं, वहां पर आश्रम है, अकेले उस गांव से इस बार तीन बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले। यानी, एक ही गांव के बच्चों ने प्रदर्शन किया है। उनमें आयुष बगड़िया, जयदीप राजपूत, लोकेन्द्र सिंह राजपूत हैं। इनमें हमारी बेटी सरोज पिपलौदा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खेलकर आई है। हमारे यहां के रहने वाले रणजीत सिंह पिपराली ने मास्टर गेम्स इटली में वर्ष 2019 में बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इनमें एक बजरंग लाल ताखर हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अर्जुन अवार्डी हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था तो हमारे सीकर में आपने इन्डोर स्टेडियम दिया है, लेकिन एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें एक एथलेटिक्स कोर्ट मिल जाए तो हमारे खिलाड़ी और आगे बढ़ सकते हैं। हम एक गांव से तीन-तीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दे सकते हैं। उस पूरे क्षेत्र में हमारा एक छोटा सा गांव है। वहां गांव के लोगों ने जन सहयोग से एक स्टेडियम बनाया है और वह जिला स्टेडियम से बेहतर बनाया है। इस प्रकार से गांव के लोग मिलकर जन सहयोग से खेल के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। मेरा सरकार और माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि खास तौर से गांव के अंदर विंग्स दी जाएं। जैसे मैंने अपने क्षेत्र के बावड़ी गांव की बात की है। वहां का विशेष खेल बास्केटबॉल है। वहां अकेले सीकर जिले ने 20 के आस-पास अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बास्केटबॉल में दिए हैं। मैं आशा करूंगा कि बास्केटबॉल और एथलेटिक्स में मेरे लोक सभा क्षेत्र में कुछ सेंटर्स खोले जाएं तो हम अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on sports. The Member who spoke earlier has already placed on record the number of medals that we have won in the Tokyo Olympics. Even though COVID-19 pandemic was there, still our athletes have done exceedingly well and they have won seven medals: one gold, two silver and four bronze. Not only in the Tokyo Olympics, even in the Paralympics as well our athletes have done exceedingly well and they have won 19 medals. They have brought laurels to the country. But at the same time, this is all focussed on getting the medals and everything.

With regard to the infrastructure that is available in the country to actually get these medals, yes, we are doing exceedingly well. The Government is doing exceedingly well. Not only the Government, even the Associations, compared to 10 years or 15 years back, have become so professionally organised right now and very transparent as well. It is because of that we can see all these results over here. But the problem is the infrastructure and the focus for us is very much on the Olympic medals and Olympic medal tally right now. The infrastructure that is being developed across the country is all focussed on that.

If we take, for example, the Gopichand Badminton Academy in Hyderabad, it has produced Saina Nehwal, P.V. Sindhu and a lot of world champions who have gone and won the medals. Also, recently I visited one of the sports facilities in Bengaluru, that is the Padukone-Dravid Centre for Sports Excellence. It is a fantastic sports facility. Anyone who goes to Bengaluru, definitely has to visit that. It is helping a lot of people to get in the sports and everything. But the problem is that all this infrastructure and all the focus from the Government is on actually getting the medals and world championships. But we must understand that sport is a holistic thing. Sport actually brings in a team spirit. Sport actually helps us understand how to get up when we fall down. These are the things that we learn. We have to learn in life; it takes a long time. But if we have to learn in sports, it is the best way to learn because whatever you learn in sports, it happens in a very short duration of time.

The reason why I am going in this direction is with regard to the usage of drugs across the country. If you see the statistics from 2017 to 2022, it has almost jumped across the country. If you see Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, anywhere if look at it, the seizures have gone up by almost 10 times. The only way that we can curb this menace is by bringing these sports to the youth at the grassroot level.

This has been done in the Scandinavian countries. If you go through the studies - the Scandinavian countries have done fantastically well - you will find that by using football they have actually brought down the alcohol abuse and drug abuse in their countries. We should take a leaf out of it. We do need medals and the world championships, but at the same time we should use sports to make sure that behavioural changes actually happen in the society. I hope, the Minister will take it up.

I have to thank Shri Anurag Thakur, even though he is not here, as I had approached him for having a sports centre in my constituency, and under the Khelo India Scheme he has sanctioned an indoor stadium in my constituency. So, I have to thank him even though he is not here. Let us not limit to one constituency. We should make sure that it actually reaches every corner of the country. It is required not just for the Olympic medals, but also to bring about a social change in the country. I hope, the Minister will take it up and make sure that it happens on the ground. Thank you very much.

श्री रवि किशन (गोरखपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे खेलों में संवर्धन की आवश्यकता पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । चूंकि हम लोग उस क्षेत्र से आते हैं, जहां पर हम लोगों के लिए खेल कुश्ती या गिल्ली-डंडा हुआ करता था । ऐसे माहौल से निकल कर आज हम लोग वर्ष 2022 में हैं, जहां यशस्वी प्रधान मंत्री, मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया के तहत, हमारे खेल मंत्रालय ने इसको एक नई उड़ान दी है, इसे एक नई ऊंचाई दी है । Where I can see कि लास्ट ईयर हम लोग बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स में आगे आए हैं । आज हमें खुशी है कि यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी की सोच के साथ एक अच्छी सरकारी योजना, खेलो इंडिया के तहत हमारे बच्चों के लिए एक बजट मिल रहा है । उसमें कुश्ती, कबड्डी, बैडमिंटन, खो-खो एवं तीरंदाजी है । नेशनल टैलेंट का एक पुल जो हमें एब्रॉड के थॉट्स में, जैसे अमेरिका में, चीन में, I always used to think why America or China get maximum gold and bronze medals. वहां पर एक योजना के तहत यह होता है कि उनकी टीम वहां के राज्यों में जाती है और एक टीम ऑफ पुल बैठी रहती है, जो अध्ययन करती है कि ये स्पोर्ट्स मेन, ये लड़के, ये बिटिया या ये लड़कियां बहुत टैलेंटेड हैं और उनका सेलेक्शन होता है और उस पर स्टडी करके उनको शॉर्टलिस्ट करके उनका नाम सेंटर में भेजा जाता है । यशस्वी प्रधान मंत्री जी की सरकार ने आज देश के बच्चों, स्पोर्ट्स मेन और इन एवरी फील्ड में एक नया विश्वास पैदा किया है । मैं आपके माध्यम से खेल मंत्रालय से भी कहना चाहता हूं कि नेशनल टैलेंट ऑफ पुल हर राज्य में क्रिएट किया जाए, जहां उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाए, बच्चों पर ध्यान दिया जाए । who are the kids, कौन बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करके खेलो इंडिया के तहत उन लोगों को फंड दे कर, we must promote them. हम उनको हर साल आगे लाएं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि every school must have, आपको स्पोर्ट्स में भाग लेना जरूरी है । आप टैलेंट के साथ आगे आएं । यह जरूरी है कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें । हमारे गोरखपुर में नौकायान प्रचलित है । हमारे यहां बहुत सारे फील्ड्स हैं । हमारे यहां झील बहुत बड़ी है । हम लोग नौकायान में आगे बढ़ सकते हैं । We have a number of football grounds. क्रिकेट के अलावा भी जो खेल हैं, देसी खेल हैं, उनमें हम आगे बढ़ें । जब यह स्कूल्स में मस्ट हो जाएगा, तो मैं स्कूल्स के बच्चों के बारे में हमेशा कहता रहता हूं कि वे ड्रग्स, अल्कोहल, शराब और सिगरेट से बचे रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे । जब वे खेल के प्रति, अपने शरीर के प्रति ध्यान देंगे, तो वे देश के लिए भी आगे बढ़ेंगे और उनका शरीर भी मजबूत होगा । इस देश में 65 प्रतिशत युवा हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी है, we have youth here. वे बचेंगे और हमें आने वाली पीढ़ी को बचाना है, वह चिंतन करना बहुत जरूरी है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं और मैं यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि सांसद स्पर्द्धा के दौरान हम लोगों ने अपने जिले में प्रतियोगिता करवाई, वह बहुत फ्रूटफुल रही । उससे बहुत अवेयरनेस आई । इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं । I must thank the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi and खेलो मंत्रालय के कारण जहां गांव-देहात के बच्चे अपने-आप को अकेला नहीं समझ रहे हैं, राज्य सरकार, पूज्य महाराज योगी जी भी प्रयास कर रहे हैं । हम लोगों का वहां पर एक बजट है । Whenever the winners come, वहां उनको अच्छा इनाम मिलता है । उनको इनाम की राशि मिलती है । उनके कपड़े किट से लेकर पढ़ाई एवं उनके फ्यूचर पर ध्यान दिया जाता है ।

मैं आपके माध्यम से बच्चों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार आपके साथ है, मोदी जी आपके साथ हैं।

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

Sports help children develop important life skills such as, leadership, discipline, teamwork, tolerance, hard work, and cooperation. Every possible sport could be played in India almost throughout the year. Yet, year after year, we fail even to qualify in most of the international sports. Many reasons like Government apathy and lack of infrastructure have been ascribed to this dreadful performance. We all must be aware of the Tokyo Olympics Bronze medallist boxer. She had complained of mental harassment caused due to constant changing of her coaches. That affected her training process for competing in the Commonwealth Games. If the athletes -- who have already reached a certain level -- are being mentally harassed, then what about those who are all still struggling? If the athletes -- who are representing our country globally -- are in such a condition, how can we expect them to bring medals and glory to the country? How can we expect that the youth will take up sports? What type of examples are we setting for the youth of the country? This is just one incident. However, there are so many such incidents where athletes have to face such issues. On the one hand, other countries nurture their athletes' talents with world-class coaching and leading advancement in sports science and technology. On the other hand, we, as a country, are not giving them their dues also.

There can be no doubt that India lacks world-class infrastructure for sports. What makes poor countries -- that are smaller than an average Indian district -- produce more Olympic Golds in a single Olympics than we have earned since the beginning of modern Olympics? In India, there is support as well as financial incentives for the top sportspersons, but the same is not true for those who are struggling to rise to the top. Sport is not just for winning medals. Children and youth need to know the positive impact of sports on the physical and mental health. When they know the importance of sports, they will more likely take up sports. The Government should provide adequate infrastructure, equipment, and human resources in schools and colleges to guide and train students in sports. Physical fitness and physical literacy should be made compulsory from the elementary schools.

Hon. Chairperson, Sir, Indian paralympic dreams are earmarked by overcoming the most challenging odds. Sports elevated their lives and those around them, but the disability and stigma they had to overcome, and the risks they took for a chance at glory are unnerving. Although India fared better at the Tokyo Paralympics than the Olympics by medal counts, the kind of support and access provided to para-athletes in the country is a stark contrast when compared to the able-bodied athletes. There is much that needs to be done to bridge this gap and hone talent no matter the disabilities present, and the Government has a crucial role to play here. Transport costs are a major hassle for para-athletes in India. A policy providing them affordable travel to sporting facilities will help massively in developing talent across the nation because access to facilities is the key. There is a need for Government's assistance in athletics and Olympic Sports to make them commercially viable. In order to further the development of emerging athletes, para-sports training facilities are essential and need to be established in every State in the next decade to capitalize on the growing popularity of para-sports. After seeing our athletes excel on the global stage, there will be more disabled youth wanting to prove their mettle on the international stage. A Central Sector Scheme by the Ministry of Youth Affairs and Sports with one of the objectives being broad-basing participative sports among the disabled can be helpful. Subsidies and grants for sports coaching institutes will ensure the retention of remarkable coaches. Technology can bring people together and generate greater participation in para-sports as well.

I would like to proudly state that hon. Chief Minister Shri K.C.R. Garu is determined to make Telangana State a sports hub and also wants to create infrastructure of international standards. He feels that there is no dearth of talent given the impressive performance of the athletes from the State. In the recent National Games, our hon. Chief Minister has also given instruction for setting up of the minimum sports facilities at the panchayat level across the State. He sanctioned Rs. 5 lakh for each panchayat. I urge the Central Government to set up Khelo India centres under Khelo India Scheme in Kamareddy district which comes under my Lok Sabha Parliamentary constituency Zaheerabad so that the athletes living in and around my Parliamentary constituency and mentioned district can get better training and can sharpen their skills and excel in sports.

Thank you, Sir.

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, मुझे यह विषय बोलने के लिए मिला है । वैसे तो सब लोग मुझे एक सिंगर-एक्टर के रूप में ही ज्यादातर जानते हैं, लेकिन अब मैं फिजिकल एजुकेशन में BPEd – Bachelor of Physical Education और MPEd करके अपनी यूनिवर्सिटी - काशी हिंदू विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा और मेरा पूरा जीवन स्पोर्ट्स से जुड़ा है । आज भी हम लोग पूरे देश में खेलों से जुड़े हुए हैं ।

आज जैसे ही खेल की बात चलती है, तो देश के यशस्वी वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने खेलों को जो मनोबल दिया है, उसके लिए भारत सरकार के खेल मंत्रालय को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद दिया जाता है । हम बहुत पहले से खेल के मैदान में रहे हैं, लेकिन हमने कहीं नहीं देखा कि खेलने के लिए जाते हुए खिलाड़ियों को देश का प्रधान मंत्री मिलता हो । … (व्यवधान) हमने श्री नरेन्द्र मोदी जी को यह करते हुए देखा है । फिर हमें पुराना समय याद आया । जब किसी ने पदक जीत लिया, चाहे वह एशियाड हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हों या ओलम्पिक गेम्स हों, अगर किसी ने पदक जीत लिया, उसके बाद हम लोगों को यदा-कदा टीवी पर उसके घर की, उसकी मां की, पिता की, बहन की कोई फोटो या वीडियो दिख जाती थी । लेकिन अब हमें दिखता है कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का फोन आया है और वे उस विजेता से बात कर रहे हैं । वह वीडियो जब वायरल होता है, तब हमें लगता है कि इस देश में खेल का भविष्य बहुत बड़ा है । … (व्यवधान)

मेरे विपक्ष के साथी यह न समझें कि मैं यह बात कह रहा हूं, तो मेरे पास सुझाव नहीं होगा । इन सारी चीजों के साथ ही आज मैं बहुत सारे सुझाव भी अपने खेल मंत्रालय के लिए रखने वाला हूं । लेकिन ये ऐसी बातें हुई हैं, जिन्होंने मनोबल बढ़ाया है । जब मनोबल बढ़ा है, तो हमें उसकी चर्चा भी करनी पड़ेगी ।

आज मुझे स्वामी विवेकानंद जी की भी एक कहानी याद आ रही है । एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास एक दुबला-पतला व्यक्ति गया और उनसे बोला कि मुझे आपको जॉइन करना है, मुझे संन्यास लेना है । स्वामी जी ने उसे ध्यान से देखने के बाद कहा कि बेहतर यह होगा कि तुम जाकर पहले फुटबॉल खेलो । उन्होंने कहा था कि जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक किसी भी फील्ड में जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा । हम लोग अंग्रेजी में सुनते भी हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है ।

सभापति महोदय, इन सबको ध्यान में रखते हुए आज जब मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा, तो मुझे इसी सदन का वह दिन याद है, जब हम लोग मणिपुर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बिल पास कर रहे थे। मुझे अगर ठीक से याद है, तो उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का लगभग 550 करोड़ रुपए का बिल था। आज उससे पूरे देश के बच्चे लाभांवित हैं। कुछ दिन पहले मेरे बिहार का एक बच्चा वहां से पढ़ाई करके आया और उसने एक जगह ट्रेनिंग देनी शुरू की है। वह बच्चा उसकी चर्चा करने लगा, फिर मुझे गर्व हुआ कि यह सरकार बहुत अच्छी दिशा में कदम भी उठा रही है और उसे एग्जिक्यूट भी कर रही है।

सभापति जी, देश में बहुत अच्छा नियम आया है कि हमारा खेल मंत्रालय ग्राउंड बनाने के लिए एक करोड़ रुपये की सहायता देता है। मुझे अपने बचपन का समय याद आता है कि गांव में जहां धान कट जाता था, उसकी डंठल को निकाल कर कुदाल से बराबर करके ईंट से दबाकर ग्राउंड बनाते थे और तब हम खेलते थे। ऐसा करने में कई बच्चों की उंगलियां भी फट जाती थीं। आज सरकार इस दिशा में ग्राउंड बनाने के लिए स्वयं आगे आ रही है। यह कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सुझाव है कि ग्राउंड बनाने का नियम बहुत सख्त है। इस नियम को यदि सहज करेंगे तो देश के प्रत्येक गांव में एक ग्राउंड देने का हमारा सपना पूरा हो सकेगा और तब हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि सांसद अपने यहां एक वॉलीबॉल का ग्राउंड बनवा दे या फुटबॉल का ग्राउंड बनवा दें तो उसकी ओट में एक से डेढ़ लाख का इजाफा हो जाता है। इस छोटी-सी बात को प्रधान मंत्री जी ने समझा और इसलिए हमारे साथी रवि किशन जी कह रहे थे कि इसी वजह से हमने सांसद खेल महोत्सव कराया। ऐसा तभी हो सकता है जब खेलों के महत्व को समझा जाए। हमने खेल महोत्सव का महत्व भी देखा। जब मैंने अपने क्षेत्र में आयोजन किया तो हमारे क्षेत्र की 8 से 12 वर्ष की 560 बालिकाएं आईं और कहने लगीं कि उन्हें खेलना है। क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा था लेकिन मैंने उन बच्चियों के लिए दौड़ का आयोजन किया। उन बच्चियों ने दौड़ में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करके उन सभी को एक-एक टी-शर्ट देनी पड़ी और तब मुझे नरेन्द्र मोदी जी की बातों का अर्थ समझ में आया कि खेल के द्वारा कैसे हम जुड़ सकते हैं।

मैं दो-तीन सुझाव जरूर देना चाहूंगा और मुझे इस विषय पर बोलने का जो समय मिला है, उसका मुझे सदुपयोग करना है। हमें अपने खिलाड़ियों को पदक जीतने तक ही सीमित नहीं रखना है। जब खिलाड़ी मैदान में जाता है तो वह अनुशासित भी होता है। अनुशासित होने के बाद उसके अंदर हार और जीत को समान रूप से स्वीकार करने की शक्ति आती है। मेरा अपना अनुभव है कि जिसने अपने जीवन में खेल को उतार लिया, वह कभी भी बेईमान नहीं हो सकता है और गलत काम नहीं कर सकता है। जैसे मेरे साथी ने कहा कि वह ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा और खेलों के द्वारा हमें व्यक्तित्व विकास को भी ध्यान में रखना है। पर्सनेलिटी डेवलपमेंट एक ऐसा विषय है जिसे लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत चिंतित रहे हैं। जैसे हमारे यहां स्पोसर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया है। यहां से हर खेल के खिलाड़ियों को सहायता करने का प्रावधान है, लेकिन मेरा एक अनुभव थोड़ा अच्छा नहीं रहा। खेल मंत्री जी बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि हमें रेस्लिंग मैट के लिए ढाई साल तक रिक्वेस्ट करनी पड़ी, फिर भी रेस्लिंग मैट नहीं मिला। इसके लिए मैंने चिट्ठी भी लिखी। मेरी प्रार्थना है कि जो सहायता दी जा रही है, उसे सिर्फ अधिकारियों तक ही सीमित न रखा जाए, उसे एग्जिक्यूट करने में नियमों को सरल किया जाए, ताकि हम सही मायने में जरूरतमंद लोगों को लाभ दे सकें। हम जिस रेस्लिंग मैट और जिस अखाड़े की बात कर रहे हैं, वहां से हमें दिव्या सेन जैसी पहलवान मिली है, जो वर्ल्ड के फोरम पर भारत के लिए पदक जीतकर लाई है। मैं वाराणसी की बात करना चाहता हूं। हमारे बनारस और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की खुशी का ठिकाना नहीं है, जब हमें 450 करोड़ रुपये का बजट मिला। वहां सिग्रा स्टेडियम है। सिग्रा स्टेडियम को पहली बार बड़े आधुनिक स्तर का स्टेडियम बनाने का काम शुरू हुआ है।

मैं अपनी तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो वहां के सांसद हैं और साथ ही खेल मंत्रालय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यह बजट निर्गत किया। इस पर कार्य शुरू हो चुका है और हमने नक्शा भी देखा है। खेल मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, अत: मेरा उनको एक छोटा-सा सुझाव है।

सर, बनारस में ऐसे और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, जिनमें थोड़ा-सा ध्यान देने से वे भी अपने-आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन सकते हैं। मैं उनकी लिस्ट भी आपको दे सकता हूं। अगर उनको इसमें शामिल कर लिया जाएगा, तो उससे बहुत बड़े स्तर पर पूरे पूर्वांचल क्षेत्र तथा वाराणसी क्षेत्र को फायदा होगा। बीएचयू के ग्राउंड्स तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन मैं तो उनकी बात कर रहा हूं, जो बीएचयू से बाहर के हैं। बाहर के होते हुए भी वे बहुत जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं। उनको हम ठीक कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मैं एक शारीरिक शिक्षक की पढ़ाई पढ़ चुका हूं और मेरा यह मानना है कि जिस तरह से भारत की खेल-नीति में परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से खेल-नीति खिलाड़ियों को सही मायने में फायदा पहुंचा रही है, वह काफी सराहनीय है। केवल ऐसा नहीं है कि जब खिलाड़ी जीत जाएं, तभी उनसे बात हो रही है, सबसे अच्छी बात मुझे यह दिखी कि खिलाड़ियों में जैसे ही क्षमता दिखती है कि यह खिलाड़ी जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ऐसी क्वालिटी दिखा रहा है, जिस पर थोड़ा अलग से ध्यान देने पर यह खिलाड़ी भारत को यश दे सकता है, तो इस पर भी खेल मंत्रालय के अधिकारी काम कर रहे हैं और उनको चिह्नित किया जा रहा है।

महोदय, इसके बाद उनके न्यूट्रीशन्स की बात आती है। मैं समझता हूं कि सदन का हर साथी बहुत खुश होगा कि जो डाइट की दर थी, उसे आज भारत सरकार ने लगभग तीन गुना बढ़ाकर खर्च किया है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं इसके लिए आदरणीय मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद भी करता हूं।

सभापति महोदय, हो सकता है कि मेरा सुझाव थोड़ा खर्चीला हो, लेकिन माननीय खेल मंत्री जी उस पर जरूर ध्यान देंगे। हमें ग्रामीण स्तर पर तथा आदिवासी क्षेत्रों में खिलाड़ियों के सिलेक्शन प्रॉसेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी भी सिलेक्शन प्रॉसेस के लिए बच्चों को अपने गांव से बहुत दूर शहर जाना पड़ता है। मेरा सुझाव यह है कि क्या हम सिलेक्टर्स को कभी-कभी गांवों में भेज सकते हैं? विभिन्न कॉम्पीटीशन्स, जो कभी-कभी आमतौर पर स्थानीय लोग या एसोसिएशन्स कराते हैं, तो क्या हमारी सरकार द्वारा यह कोशिश हो सकती है कि हम सिलेक्टर्स को गांव-गांव या गांवों के समूह तक भेजें?

सर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जब हम लोगों का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, उस दौरान कई लोग ऐसे होते हैं, जो अपनी क्षमता नहीं जानते हैं कि उनके अंदर कितनी ऊर्जा है। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए थे, जो अब चले गए हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग वेलनेस सेंटर्स गांव-गांव बना रहे हैं, अगर उन सेंटर्स पर हम खिलाड़ियों की क्षमता का भी टेस्ट करने लगें, तो भी हम बेहतर खिलाड़ियों को आगे निकाल सकते हैं। अंत में मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि ये बातें हम तभी कह रहे हैं, जब हमें आशा जगी है। मेरी कई खिलाड़ियों से बात होती रहती है। मैं समझता हूं कि इस दौर में जिस तरह से खेल मंत्रालय काम कर रहा है, आदरणीय मोदी जी जिस सकारात्मक रूप से इसे ले रहे हैं, उससे मुझे बहुत आशा है तथा यह आशा और बढ़ी है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमती *m09 नवनित रवि राणा (अमरावती): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

पहले तो मैं हमारे खेल मंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनन्दन करना चाहूँगी कि खेल की इस दुनिया में जहाँ पर खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, वहाँ पर हर जगह खुद मंत्री महोदय उपस्थित रहकर उन्हें हर चीज पर सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले तो मंत्री महोदय का धन्यवाद करूँगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ सुझाव हैं। अभी नेशनल स्कूल्स, जो बच्चे जाकर खेलते थे। स्पोर्ट्स स्कूल्स के द्वारा खिलाड़ी, बच्चे जाकर खेलते थे, नेशनल और इंटरनेशनल के झगड़े में इस साल वह नेशनल स्पोर्ट्स नहीं होगा। यह मामला सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस साल स्कूल के बच्चे जाकर खेल नहीं पाएंगे तो इसमें उन बच्चों की क्या गलती है। इस तरह के आपसी झगड़ों में इस साल बच्चों का नुकसान न हो, या तो वे नेशनल वाले खिलाएं, नहीं तो गवर्नमेंट को उसे टेकओवर करके बच्चों को खिलाना जरूरी है। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए और बच्चों का इस साल गेम खराब नहीं होना चाहिए। इस पर हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।

अभी मनोज तिवारी जी ने बहुत अच्छा कहा है। आदिवासी क्षेत्र मेरे जिले में आता है। जिस तरीके से खेलो इंडिया के माध्यम से हर जिले में इसका एक सेंटर दिया गया है कि हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, वे प्लेन पट्टों से करीबन 120 किलोमीटर, 130 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहरी क्षेत्र में आएंगे और अगर उन्हें खेलो इंडिया के सेंटर में आना है, तो वहाँ उन्हें रहने की व्यवस्था नहीं मिलती है या उन्हें खाने की व्यवस्था नहीं मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे खेल खेलते हैं, अगर इस सेंटर में उनके रहने और खाने की व्यवस्था होगी तो मुझे लगता है कि

उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा और वे खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जितने मेडल्स देश के लिए आवश्यक हैं, मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, लड़के अच्छा खेलकर उन मेडल्स को लाकर दे सकते हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से जितने भी हमारे बच्चे खेलो इंडिया में मेडल जीतकर आते हैं, बाकी खेलों के माध्यम से तो खिलाड़ियों को आरक्षण देकर उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वे बच्चे बहुत साल ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें जॉब्सै मिलती है तो उन्हें फुलफिल लगता है कि हमने खेला, हमने देश के लिए खेला, हम देश के लिए मेडल्स लाए तो हमारी लाइफ सरकार और हमारी मेहनत के द्वारा बनी है। खेलो इंडिया में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। या तो इन गेम्स को भी आरक्षण में लाया जाए, जिनको खेलो इंडिया में मेडल मिले हैं, या फिर उन्हें डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। मुझे लगता है कि ऐसा होने से खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे देश के खिलाड़ियों को बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। अदरवाइज छोटी-छोटी चीजें हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, उन्हें छोटी-छोटी चीजों की आवश्यकता रहती है। अगर डिमांड के अनुसार उन्हें पूर्ण करने का हमने प्रयत्न किया तो आने वाले समय में देश में हमें जितने खिलाड़ी अपेक्षित हैं, उससे कहीं ज्यादा खिलाड़ी हमारे देश को मिलेंगे।

मैं इतनी ही आपसे विनती करूँगी। खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए, आप जो खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं सरकार और हमारे मंत्री महोदय का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी।

सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I am starting my speech by welcoming the discussion on the need to promote sports in India. I think it is the right time to discuss this matter. The football World Cup, 2022 in Qatar has come to its final stage and we have to learn so much from Qatar. Qatar is a small country. It has developed its sports infrastructure very much and it is conducting that mega event very successfully.

Sir, we have the strongest youth force in the world. We have that advantage. But we have not got as much success in sports sector as we expected. I think that is the subject of today's discussion. We have to give much focus on this matter.

We have to learn from the successful stories of other countries, about their management, their policies, their sports education etc. We have conducted so many mega events like Asian Games, Commonwealth Games and other sports events also. But in regard to budgetary allocation, I feel that we are giving secondary treatment to the Ministry of Youth Affairs and Sports. We are giving much importance to other Ministries. I am not saying that it is a mistake. I feel that we are not giving enough importance to the Ministry of Youth Affairs and Sports. In the last Budget, we allocated only Rs.362.60 crore to this Ministry.

There is a slight difference in the Budget from that of the last year. We have to develop more facilities in our sports academies. We are following all our sports developments like sports education and practices etc., through our sports academies.

In my knowledge 'Khelo India Programme' is also another scheme for the development of spots in India. It is also a sports academy. But we have to attach much more importance to it.

I would make some suggestions for development of the sports academics. All the sport academies are concentrated in townships. Mega events and sports stadiums may be there in the townships, and it is a welcome step. But the practicing academies should be concentrated in the village areas. Then only, we would get the advantage of more and more sports persons. Their physical strength and stamina, in a real sense, is connected with or related to village-wise rural sports.

Sir, I come from Idukki District. It has a good sports culture. We have a sports tradition there. But all this is not being utilised fully. The reason is that our sports infrastructure is not fully developed. So, if we start developing our sports infrastructure and practicing grounds in the rural areas, especially in the hilly areas, definitely we would get many advantages. In my knowledge, the Sports Authority of India in 2014, had a plan to start one High Altitude Training Centre in Munnar in my Constituency. Munnar is the highest peak in South India. I have gone through the minutes of the Sports Authority of India. The hon. Minister may be aware about it. But I find that, they have not even started the process. The Government is always saying that there are financial constraints.

In his speech, my colleague Shri Manickam Tagore also mentioned about the Public Private Partnership in sports. We have to welcome the private parties to help the sports sector. Already many private parties are investing money for the development of sports infrastructure. But we should have a proper plan to welcome more and more private parties to do investment in sports infrastructures in PPP mode. It would really be a welcome step. So, Sir, I am once again demanding for setting up of a High Altitude Training Centre in Munnar. It will be of great advantage to our nation because the physical strength and stamina are connected with the practice of sports persons in the High Altitude Training Centres. In the end, I would say that we should have a proper plan about imparting sports education to our students in our colleges and universities. So, we should think of starting a Centre of Excellence in our universities. We should also think of starting sports science courses and laboratories in our universities. We should extend the services of sports sciences by including sports psychology, sports medicines, performance analysis and human performance labs. Coaching for elite athletes through foreign specialists is also very much necessary. We should think about it seriously. Sir, sports is uniting the nation. Apart from politics, be it caste, creed or anything, we are all united when it comes to sports. Whatever developments are coming in the sports sector, we should welcome them, and we will support them even being in the Opposition.

With these few words, I am supporting this discussion on sports under Rule 193. Thank you.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सर, आपने मुझे नियम 193 के अंतर्गत स्पोर्ट्स की चर्चा में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मंत्री जी खुद एक बढ़िया क्रिकेटर रहे हैं । मुझसे पूर्व भी सांसदों ने बात की है कि कहीं भी स्पोर्ट से संबंधित कोई भी इवेंट हो, तो मंत्री जी वहां पहुंच जाते हैं और वहां जाकर खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाते हैं । मैं इस बात के लिए इनको बहुत मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि देश के नौजवानों की और देश के स्पोर्ट्स वालों की मंत्री जी हिम्मत बढ़ाते हैं ।

सर, अभी मनोज तिवारी जी बोल कर गए।... (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी: मैं यहां बैठा हूं।

श्री मलूक नागर: अच्छा । अभी यहां बैठे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रिकेट का एक टूर्नामेंट कराया था। मैं आज सब के सामने यह कहना चाहता हूं कि मैं भी क्रिकेट का प्रेमी हूं और मैच देखता हूं। लेकिन देश के जो महत्वपूर्ण अलग-अलग तरीके के खेल हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। अकेले एक क्रिकेट के खेल में, चाहे बीसीसीआई हो या आईसीसी हो, उनके एकाउंट में हजारों-करोड़ रुपये पड़े रहते हैं और हमारे दूसरे लोग जो गोल्ड मैडल लेकर आते हैं, उनको ऐसी-ऐसी सुविधाओं की दिक्कत होती है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

अभी क्रिकेट की बात चल रही है। सन् 1983 वर्ल्ड कप के बारे में मुंबई में एक बुक लॉन्च हुई थी। उस समय देश में फोटो नहीं थे तो विदेशों से मंगवा कर लॉन्च की गई। मेरी किरमानी साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनको सुविधा मिली थी कि जो वर्ल्ड कप जीत कर लाए हैं, हमेशा वे लोग, आजीवन ट्रेन में फ्री यात्रा करेंगे। उनको थर्ड ए.सी. की सुविधा मिलती है। क्रिकेटर या देश के नामचीन एथलीट एवं खिलाड़ी अवॉर्डी रहे हैं, सरकार उनकी सुविधाओं पर भी ध्यान दे।

आज देश 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक हिस्सा 20 पर्सेंट देश का है और दूसरा 80 पर्सेंट का है। 20 पर्सेंट वाले में शहरी लोग हैं और 80 पर्सेंट वालें में गांव-देहात के लोग हैं, जहां पर इंटरनेट नहीं है। जो अभी गद्दों की बात तिवारी जी ने कही है, वहां उन लोगों को सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। सरकार इस तरफ सोचे। जितना सरकार आज लगातार आर्थिक दृष्टि से तरक्की करती जा रही है और वर्ल्ड के पैमाने पर अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों को पछाड़ती हुई आगे बढ़ रही है, मैं चाहता हूँ कि गांव-देहात से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ इतना ध्यान दिया जाए, ताकि वे भी हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। एक तरफ हम आगे बढ़ जाएं, वहीं खिलाड़ी पिछड़ जाएं, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए और उनको पूरी सुविधाएं दी जाएं। चाहे सरकार किसी भी टैक्स को कहीं से भी लगा दे और देश के खिलाड़ियों को चिन्हित कर के हर प्रदेश के जो-जो खिलाड़ी एक नंबर से 10 नंबर के हर राज्य में हैं, उनको इतनी सुविधाएं दें कि उनकी इतनी हिम्मत बढ़े, इतना मनोबल बढ़े, जिससे वे वर्ल्ड के पैमाने पर अपने देश का नाम ऊंचा कर सकें।

दूसरा, खास कर जम्मू-कश्मीर है, जहां धारा-370 हटने के बाद, जो लोग देश की बाउंड्री पर रहते हैं, जो गुर्जर-बक्करवाल हैं, देश की सीमा पर रहते हैं, उनको थोड़ी ज्यादा सुविधाएं दी जाएं। दूसरे प्रदेशों में भी जैसे पंजाब, राजस्थान हैं, जिनकी सीमा दूसरे देशों के साथ लगती हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, जिससे उनको भी लगे कि हम भी इस देश का हिस्सा हैं।

जहां तक बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आती है, जहां से मैं चुनाव जीत कर आता हूँ, वहां पर मेरठ है, एक समय था कि जब मेरठ, आगरा और दिल्ली बराबर की हैसियत में होते थे। पिछले दिनों यूपी में कमिश्नरेट की सुविधा कई जिलो में दी गई, जिसमें आगरा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले हैं, लेकिन मेरठ को छोड़ दिया गया।

मेरठ के चारों तरफ सहारनपुर लोक सभा क्षेत्र है, मुज्जफरनगर लोक सभा क्षेत्र है, बागपत लोक सभा क्षेत्र है, बिजनौर लोक सभा क्षेत्र है, अमरोहा लोक सभा क्षेत्र है, गाजियाबाद लोक सभा क्षेत्र है, नगीना लोक सभा क्षेत्र है। मेरठ जिले में और जो ऐतिहासिक हस्तिनापुर जगह है, वहां पर हज़ारो बीघा जमीन चरवाहे की खाली पड़ी हुई है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वहां स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बनाया जाए और मेरठ को भी पहले की तरह दूसरे प्रदेशों जैसे दिल्ली और आगरा की तरह देखा जाए। साथ ही चारों तरफ की जो लोक सभाएं हैं, अमरोहा हो, नगीना हो, मेरठ हो, बागपत हो, मुज्जफरनगर हो, बिजनौर हो, गौतम बुद्ध नगर हो, गाज़ियाबाद हो, वहां पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि वहां के लोगों को भी सुविधा मिल सकें और वे देश की तरक्की में, खेल से संबंधित क्षेत्रों में वे भी हिस्सा ले सकें।

धन्यवाद।

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Thank you, Sir, for permitting me to take part in this very important discussion. Sir, this is a very timely and meaningful discussion. We are discussing this important issue at a time when the world-renowned FIFA World Cup celebration is coming to an end worldwide in Qatar in a very brilliant and magnificent manner. This discussion will help our process and attempt to make our country a superpower in the field of sports. We will be able to achieve that aim if we work hard with a clear plan of policy making.

Sir, sports play a very major role in achieving the Sustainable Development Goals. Nowadays, sports are identified as the biggest player in achieving the Sustainable Development Goals. So, access to sports should be ensured to everybody. Then only, we will be able to achieve more and more in the arena of sports. Sir, people belonging to lower income levels have a very limited access to sports opportunities. So, there must be a supportive legislation to ensure the entry of lower-class people to sports. There was a report submitted by the London School of Economics which found that cost was the biggest barrier for young people to participate in sports because of their financial ability and economic backwardness.

That has to be taken into consideration, and for that, a legislation has to be made. Sir, the link between sports and development has to be identified and realised by our policy makers. It has to become a part of our development budget. Funding of sports-related projects is a practice in progressive countries like Germany, Austria, Norway and Japan.

We need to adopt that model. India is the second largest country in terms of population and also the biggest democracy. But why are there only a few medallists in our country? That is a very important issue we have to ponder upon. Indian Cricket and Hockey teams are one of the finest teams.

There is no doubt about that. We have very brilliant sportspersons. But still, due to many basic reasons and because of our own policies, we are not able to make great achievements in this field.

A huge number of Indian football fans were very eager to see our country playing in FIFA World Cup in Qatar. But it is unfortunate that nowadays, sports have become a medium of cordial meeting between nations. Still, we have to go far beyond to realise our goals.

Sir, the most important thing I feel is the necessity of physical literacy. It must be recognised as a fundamental right. Amicus Curiae had submitted a report in the beginning of this year at the Supreme Court asking every educational board, including CBSE and ICSE to ensure at least 90 minutes of their time to be dedicated to free play and games. That was given in the report. But no action has been taken on these kinds of recommendations and suggestions.

Sir, sports are never a priority of majority of Indian parents and kids. That is our problem. Even now, most of the Indians believe that if they study hard, they will be successful and if they play sports, they will ruin our life.

Sir, if we really want to solve the problems related to sports, we have to take certain points into consideration. I have certain suggestions. Poverty is one of the reasons. Also, it is not easy to pursue a career in sports for many of our young men and women. The infrastructure is also poor. School sports and College sports are not made a part of the educational system.

Also, there is a lack of coaches to nurture and groom talent. Cricket continues to dominate the landscape of other Indian sports. All other types of sports are being ignored.

I would like to draw the attention of our hon. Minister to pay equal attention to many other unidentified and unencouraged areas of sports. The attitudes of the corporates and the wealthy individuals need to be changed in this regard.

Sir, another problem is corruption. Many of the governing bodies of sports organisations are led by politicians who have little knowledge about sports. Most of them have nothing to do with sports. This kind of unprofessional approach is responsible for this kind of a downfall.

16.00hrs

I believe that this is an age of lifestyle diseases. If physical education is brought into the curriculum and every Indian citizen is given a chance to enter into the sports field, it will be helping us to meet the challenges of lifestyle diseases.

Finally, I have a request to the hon. Minister. My constituency and the district, which I represent, is Malappuram. It is very famous for football lovers and football-related activities. Many of our young men and women are very much interested in football. We have good players. We have contributed both good sportsmen and sportswomen even to Olympics.

So, we want more and more football stadiums in the district of Malappuram. Further, we would like to have more encouraging schemes and programmes, especially in the area of Malabar, and in Kerala, for encouraging sports.

I would like to request the hon. Minister to pay his attention to this kind of a demand from a backward region so that they can also be brought to the mainstream of our sports activities. Thank you, Sir.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, मैं एक बार पुन: आपका आभार व्यक्त करता हूँ ।

माननीय सभापति जी, खेलों की ओर विशेष रूप से वर्ष 2014 के पश्चात, जब से माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा-एनडीए की सरकार आई, तब से बहुत विशेष ध्यान दिया गया। चाहे वह सुविधाएं उपलब्ध कराने का विषय हो, चाहे वह नीतिगत मामले हों, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हो, प्रत्येक दृष्टि से ध्यान दिया गया है।

16.01hrs (Shrimati Rama Devi in the Chair)

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का वैशिष्ट्य यह होता है कि वह किसी भी विषय को संपूर्णता के साथ देखते हैं और उस पर विचार करते हैं। उसके प्रत्येक अंग को स्पर्श करते हुए उसके विकास का एक खाका तैयार करते हैं, फिर उसको कुशलता के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। खेल से जुड़ा हुआ प्रत्येक विषय उनकी दृष्टि में रहा है। इसलिए, धन का जो आबंटन है, वह निरंतर

बढ़ा है। जैसा मैंने कहा कि खेल की सुविधाएं बढ़ी हैं, आज 'खेलो इंडिया' के माध्यम से पूरे देश में खेल का एक वातावरण बना है।

अभी गत वर्ष एक कार्यक्रम हुआ, जिसकी उन्होंने प्रेरणा दी। हमारे खेल मंत्री जी ने उसके विषय में बहुत उत्साहपूर्ण ढंग से सबसे चर्चा की। जो 'सांसद खेल' प्रतियोगिताएं हुईं, उन सब से भी खेल के लिए देश में बहुत ही अनुकूल वातावरण बना है। हमें इसका परिणाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अंदर दिखायी देखता है। हमारे मेडल्स की टैली बहुत इम्प्रूव हुई है। हम निरंतर प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते जा रहे हैं। हमारे 'उड़न सिख' मिल्खा सिंह जी की इच्छा थी कि एथलेटिक्स के अंदर कोई मेडल प्राप्त हो। अब माननीय मोदी जी की सरकार बनने के पश्चात के वर्षों में गत वर्ष पूरा हुआ है। हम अद्भूत गति और निरंतर खेलों की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने खेल मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही जो संपूर्ण टीम है, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ।

मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने कहा कि खेल केवल मेडल के लिए या कुछ उस प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त करने के लिए नहीं है और केवल इसके लिए उसको प्रोत्साहन देना आवश्यक नहीं है। वास्तव में, सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व की दृष्टि से भी खेलों का बड़ा भारी महत्व है। यदि खेल है तो व्यक्ति के अंदर एकाग्रता का निर्माण होता है। वह कैसे अपने शरीर, मन और बुद्धि को एकाग्र करके ठीक ढंग से उपयोग करे, क्योंकि उसके बिना सफलता नहीं मिलती है।

यह जो गुण का विकास होता है, इस प्रकार के जो गुण विकसित होते हैं, वे जीवन के अंदर भी काम आते हैं। इसी प्रकार से जीत-हार को समान रूप से देखना चाहिए। जो खिलाड़ी खेल रहा है, बहुत बार वह हारता भी है, बहुत बार जीतता भी है। इसी प्रकार से टीम स्पिररिट भी जरूरी है। इंडीविजुअल स्पर्धायें होती हैं, लेकिन टीम स्पर्धायें भी होती हैं। टीम स्पर्धा के अंदर, हॉकी है, फुटबाल है, किसको कैसे पास देना है, कबड्डी है, क्रिकेट है या टीम के जो खेल हैं, उसमें यदि खिलाड़ी के अंदर टीम भावना नहीं होगी और वह अपने ही प्रोजेक्शन को ध्यान में रखकर खेलेगा तो उसकी टीम नहीं जीतती है। टीम की जो भावना है, वह भी खेल के द्वारा विकसित होती है। इस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण करने की दृष्टि से भी खेल का बड़ा भारी महत्व है। इस नाते खेलों को जो प्रोत्साहन दिया गया है या निरंतर दिया जा रहा है, मैं समझता हूं कि उसका बहुत ही अभिनन्दनीय परिणाम पूरे देश के अंदर दिखाई देता है।

मैं यदि मेरठ की दृष्टि से बात करूं, तो मेरठ खेलों के सामान के उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है। क्रिकेट तो जरा ज्यादा चर्चित है, क्रिकेट बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, इसलिए उसके बल्लों की बातें जरा ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन उसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई ब्रांड्स मेरठ के अंदर निर्मित होते हैं, चाहे टेबल टेनिस का हो, एथेलेटिक्स का हो या अन्य स्पर्धायें हों। विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण हमारा सामान मेरठ के अंदर बनाया जाता है। प्रदेश सरकार ने ओडीओपी योजना में, वन डिस्ट्रि क्ट, वन प्रोडक्ट योजना में उसके अंदर खेल को ही मान्य किया है। हालांकि, मेरठ के अंदर और भी बहुत सारी चीजों का उत्पादन होता है, लेकिन ओडीओपी के अंदर खेल को ही उन्होंने मान्य किया है।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्होंने भी हमको इस कारण से कह लीजिए या खेलों की जो गतिविधियां मेरठ के अंदर होती हैं, उसके कारण से कह लीजिए, उन्होंने भी मेरठ को एक प्रकार का आशीर्वाद दिया है कि मेरठ में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की घोषणा हुई। उसका शिलान्यास माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा गत् 2 जनवरी को किया गया। बहुत अच्छे ढंग से खेल का एक बड़ा विश्वविद्यालय मेरठ के अंदर बनने जा रहा है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने, जितने भी पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने उसके अंदर मैडल जीते, जिन्होंने उसके अंदर भाग लिया, सबके सम्मान का कार्यक्रम मेरठ के अंदर किया। उसके कारण से भी खेल की गतिविधियों के विषय में जिज्ञासा, उसके प्रति उत्साह पूरे मेरठ में और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर निर्माण हुआ। मेरठ के बारे में इस बात का भी मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि मेरठ खेल सामान के उत्पादन में तो अग्रणी है ही, परन्तु विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छे खिलाड़ी भी मेरठ ने निरंतर दिए हैं। चाहे वह कुश्ती हो, चाहे वह तीरंदाजी हो, शूटिंग हो, हॉकी हो, यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेरठ के अंदर निर्मित हुए हैं। मेरठ का बड़ा सौभाग्य है कि मेजर ध्यानचंद बहुत समय तक मेरठ के अंदर सेना के अधिकारी के रूप में वहां पर रहे। उनके कारण वहां पर हॉकी को बहुत प्रश्रय और प्रोत्साहन मिला।

मैं एक-दो बातें मेरठ को लेकर कहना चाहता हूं। इतने सारे वैशिष्ट्य के बाद भी मेरठ में अभी तक भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं बनाया गया है। मेरा माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज़ बनायें, जिससे कि सब प्रकार की अन्य सुविधायें उसको प्राप्त हो सकें। "खेलो इंडिया" योजना के अंतर्गत वहां पर एस्ट्रोटर्फ का चार साल से निर्माण चल रहा था। अब उसका लोकार्पण हो चुका है। अब उसमें टूनामेंट्स होने लगे हैं। अगर एस्ट्रोटर्फ के संबंध में देश की आजादी के बाद जरा तेजी से कुछ काम किया होता तो जो बादशाहत हमारी हॉकी के अंदर पूरी दुनिया में बनी हुई थी, उसमें इतनी जल्दी कमी नहीं आती। सारी दुनिया के अंदर जो मैचेज़ हैं, वे एस्ट्रोटर्फ पर होते हैं। उसके अंदर एस्ट्रोटर्फ बनाने में हमारी थोड़ी गति धीमी रही। मुझे यह कहते हुए कोई खुशी नहीं हो रही है कि मेरठ के अंदर जो एस्ट्रोटर्फ बना है, वह केवल दूसरा एस्ट्रोटर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर है। इनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी। आज सारे खिलाड़ियों को एस्ट्रोटर्फ पर ही अभ्यास करना पड़ता है। उसके अंदर अभ्यास करेंगे तभी वह अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के अंदर यशस्वी हो सकते हैं। यह अच्छी बात है कि मेरठ के अंदर एस्ट्रोटर्फ का निर्माण हुआ, वह वहां पर लगा और उसके ऊपर प्रतियोगितायें हो रही हैं। साथ ही साथ, मेरठ ने एथेलेटिक्स के अंदर भी बहुत से खिलाड़ियों को दिया है। तेज चाल के अंदर प्रियंका गोस्वामी हैं या दौड़ प्रतियोगिता के भी कई खिलाड़ी दिए हैं।

परंतु वहां पर सिंटेथिक ट्रैक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि कैलाश प्रकाश स्टेडियम या अन्य किसी स्थान पर सिंथेटिक ट्रैक बन जाएगा तो उसका लाभ सभी प्रकार के खिलाड़ियों को अभ्यास की दृष्टि से मिलेगा। मैंने एक विषय को पहले भी संसद के अंदर उठाया था, खिलाड़ियों को खेलते समय छोटी-मोटी इंजरी हो जाती है, वह इंजरी सामान्य चोट से थोड़ी अलग होती है, उनको अलग प्रकार से देखभाल करने की जरूरत होती है। एक बात आई कि प्रत्येक स्थान पर खेल मंत्रालय द्वारा संभवत: स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बनाने की स्थिति नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है कि सामान्यत: मैं उत्तर प्रदेश के बारे में तो कह ही सकता हूं, प्रत्येक जनपद के अंदर मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और खोले जा रहे हैं, कमिशनरी लेवल पर बड़े-बड़े हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की एक व्यवस्था की जाए कि जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें स्पोर्ट्स इंजरी को देखने के लिए एक डेडिकेटेड वार्ड हो, जो उसके एक्सपर्ट्स हों, जो उसकी चिंता करें। यदि किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो उसकी व्यवस्था की जा सके और उस खिलाड़ी का खेल जीवन चोट के कारण बाधित न हो। वह स्वस्थ होकर पुन: अभ्यास कर सके, उसको और भी सहायता दी जा सकती है। स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर मेडिकल कॉलेजों के अंदर डेडिकेटेड रूप में बनाए जाएं तो उसकी व्यवस्था सुगमता से हो सकेगी। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और हमारे खेल मंत्री जी के सक्रिय निर्देशन में खेल का वातावरण बन रहा है, वह अद्भुत है। हमें पूरा विश्वास है कि खेल का वातावरण निरंतर बहुत अच्छा होगा, हम प्रत्येक खेल के अंदर दुनिया में बहुत अच्छा यश प्राप्त करेंगे।

मैं इस चर्चा को सदन में कराने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मुझे अवसर देने के लिए आपका पुन: अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): मैडम चेयरपर्सन, आपने मुझे नियम 193 के अंदर स्पोर्ट्स चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। देश में स्पोर्ट्स को अच्छा करने के लिए क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि किसी भी देश का चेहरा देखना हो तो खेल से देख सकते हैं। उसके अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कितने खिलाड़ी स्वर्ण पदक ले रहे हैं, कितने सिल्वर पदक ले रहे हैं, कितने ब्राउंज पदक ले रहे हैं। उससे हम उसकी सेहत और अर्थव्यवस्था का अंदाजा भी लगा सकते हैं। देश में अभी तक जो भी

खिलाड़ी खेलकर पदक लेकर आया है, मेरा मानना है कि या तो वह बहुत गरीब तबके से आए हुए लोग हैं या गांव से आए हुए लोग हैं, जहां खेल की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां चर्चा करते हैं तो यह दिखाया जाता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है ।

मैं माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करूंगा कि जहां कहीं भी जरूरत होती है तो वह वहां पहुंचते हैं और काम करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन जब तक आप सही बजट खेलों के लिए नहीं रखेंगे, जब तक आप जमीन पर जाकर उसे क्रियान्वित करने की कोशिश नहीं करेंगे तो देश स्वर्ण पदक से ऐसे ही दूर रहेगा । अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि हमने ओलंपिक में 7 पदक लिए हैं, हमसे छोटे-छोटे देश जैसे क्रोएशिया, वेनजुएला और अर्मेनिया है, लेकिन उनके पास हमसे से ज्यादा पदक हैं । 125 करोड़ की आबादी में इतने कम पदक आना चिंता का विषय है ।

खेलों में आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन और अच्छा करने की जरूरत है । जैसे हम ट्रिलियन्स डॉलर इकोनॉमी खड़ा करना चाहते हैं । अमेरिका और चीन है, चीन ने इस समय 88 मेडल जीते हैं, हमने सात पदक लिए हैं । हमें चिंता करनी चाहिए, आप खेलों के लिए वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं । पंजाब खिलाड़ियों की धरती थी, हरियाणा में कितने पदक आ रहे हैं, वह भी कभी पंजाब का ही हिस्सा था । उन्होंने अच्छा काम किया लेकिन पंजाब में भी अच्छा काम होना चाहिए । इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान हमें हर समय डिस्टर्ब करता है, कभी ड्रग्स के जरिए या कभी और किसी न किसी तरीके से वहां का माहौल खराब करता है ।

हमारी आपसे विनती है कि यदि आप काम करना चाहते हैं तो गांव में ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम खोलिए । जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय महाकुम्भ होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स होता है । आप कोशिश कीजिए कि राजधानी के अलावा प्रदेशों के रूरल एरिया में भी लेकर जाइए, जब आप स्टेडियम बनाएंगे, मेरा मानना है कि आपने यहां स्टेडियम बनाया है, सिवाय टूर्नामेंट के कोई भी खिलाड़ी वहां नहीं पहुंच पाता । यदि आप यही स्टेडियम अमृतसर में बनाएंगे, फिरोजपुर में बनाएंगे या बॉर्डर एरिया में बनाएंगे तो वहां के लोगों में जान है, उनके पास टाइम भी है, आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो वहां से अच्छा रिजल्ट आ सकता है ।

अब अमृतसर की बात करते हैं, मेरा संसदीय क्षेत्र है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 1947 से पहले नेशनल वन डे ट्राफी, इंटरनेशनल मैच थ्री डे मैच में अमृतसर के 13 क्रिकेट प्लेयर्स थे । वर्ष 2016 में जितनी रणजी ट्राफी हुई हैं, उनमें और वन डे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल और आईपीएल में अमृतसर के प्लेयर्स हैं । जब स्टेडियम की बात आती है तब वह दिल्ली में बन जाता है । चलो ठीक है, आप यहां भी बनाइए । क्यों आपका ध्यान अमृतसर की तरफ केंद्रित नहीं होता है?

महोदया, जितने भी वार्ड्स हैं, आप चैक कर लीजिए । अर्जुन अवार्डी ओलिंपियन गुरबचन सिंह रंधावा को वर्ष 1921 में अवार्ड मिला । आप मिलखा सिंह तक देख लीजिए, लंबी लाइन है । उडना सिख की चर्चा सांसद कर रहे थे, वह अपनी मेहनत के साथ वहां तक गए थे । हमने संसद में कई बार अमृतसर की बात रखी कि यहां के लिए अच्छे स्पोर्ट्स स्टेडियम और वैलनेस सैंटर की जरूरत है । महा पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी एशियन गेम्स के प्लेयर, साउथ एशिया की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, ओलंपिक्स में अंडर इंटरनेशनल जितनी भी कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं, उनमें अमृतसर का बहुत बड़ा रोल है । यहां बहुत बड़े खिलाड़ी पैदा हुए हैं । बच्चे, जो आगे खेलना चाहते हैं, उनके फ्यूचर के लिए सरकार की तरफ से एक अच्छा वैलनेस सैंटर और अच्छा स्पोर्ट्स सैंटर बन सकता है, अच्छी यूनिवर्सिटी बन सकती है । देश का नाम तो हम सबने मिलकर करना है । रेस्लिंग हो, बॉस्केट बॉल हो, एथलेक्टिक्स हो, फुटबाल हो, जिम्नास्टिक्स हो या हॉकी हो, हॉकी बहुत बड़ा गेम है, लेकिन एक ही एस्ट्रोटर्फ है ।

महोदया, मैं स्पीकर साहब के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैंने यहां अच्छा स्टेडियम 'खेलो इंडिया' के तहत बनाने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक वह बना नहीं है । यदि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें नेशनल लैवल पर सुधार करने की जरूरत है ।

आपको पता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन बार-बार कह रही है कि आप इलैक्शन कराएं, लेकिन इलैक्शन नहीं हो रहे हैं । आप इलैक्शन नहीं कराएंगे तो फीफा वर्ल्ड कप में भी नहीं जा पाएंगे । इंटरनेशनल हॉकी वर्ष 2023 में आ रही है । इंटरनेशनल मैच में आप नहीं जा पाएंगे । हमें इन बातों की तरफ ध्यान देना होगा । ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी एज़ भी खेलने की नहीं है । मेरा ख्याल है कि वे ग्राउंड में भी नहीं गए होंगे । राजनीतिक लोग, रिटायर्ड अफसरों की सैरगाह बन चुकी है, होल्ड करने की जगह बन चुकी है, जब वे रिटायर हो जाते हैं तो उनको बिजनेस क्लास की टिकटें चाहिए, फाइव स्टार होटल चाहिए तो हमारे प्लेयर्स के ऊपर खड़े होकर खिलवाड़ करके बैठे हैं । इन सबको वहां से निकालिए, हम आपका साथ देंगे । जितने इलैक्शन पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप इलैक्शन को कम्पलीट कीजिए नहीं तो आप वहां खेल नहीं पाएंगे । कई जगह इल्जाम लगते हैं, टीमों पर इल्जाम लगते हैं । प्लेयर्स का क्या है, वह तो मेहनत करके नेशनल और इंटरनेशनल लैवल तक पहुंचते हैं, बड़े धुरंधर लोगों पर इल्जाम लगते हैं । क्रिकेट में भी लगते हैं, टेबल टेनिस में भी लगते हैं । आपको इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है । सरकार इस तरफ ध्यान दे ।

अब पेरालंपिक की बात आती है । पेरालंपिक वे बच्चे खेलते हैं जिनको अंग की प्राब्लम होती है, उन्हें अंगहीन कह सकते हैं, उन्हें स्पेशल चाइल्ड कह सकते हैं । जब ओलंपिक्स में बच्चे जीतकर आते हैं, उनका फ्यूचर क्या है? उनको जॉब मिलेगी तो कब मिलेगी? इसका कोई प्रावधान नहीं है । मेरी मंत्री जी से दरख्वास्त है कि पेरालंपिक के अमृतसर में बहुत प्लेयर्स हैं, दुबई से मेडल जीतकर आए हैं, लेकिन उनके फ्यूचर के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है कि वे आगे क्या करेंगे ।

महोदया, स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा मिलती है, लेकिन इसका स्पोर्ट्स अंग नहीं बना है । जब तक स्पोर्ट्स की शिक्षा कम्पलसरी नहीं की जाएगी, अच्छे कोचिस पैदा नहीं होंगे, अच्छे खिलाड़ी पैदा नहीं होंगे । अब कोच लेने हैं तो पंजाब की बात कर लें । पंजाब के पास कोच की कमी रहती है । कहां से लेते हैं, पंजाब आर्म्ड पुलिस फोर्स से लेते हैं ।

हम लोग पीएपी से कोच लेते हैं । वह कोच कब आएगा? कभी सरकार की तरफ से उसको बुला लिया जाता है । लेकिन, उससे प्लेयर का बहुत बड़ा नुकसान होता है । एक प्लेयर अपनी जिन्दगी में अपने परिवार की पूरी पूंजी, अपना पूरा ध्यान और अपना पूरा समय अपने खेल को अच्छा करने के लिए लगा देता है । जब वह मेडल लेकर आता है तो मेरे जैसा लीडर जाकर उसके साथ फोटो खिंचवाता है और कहता है कि इसने हमारी वजह से देश का बड़ा नाम कर दिया है । लेकिन, उसने जो 10 साल, 15 साल और 20 साल का समय खेल के मैदान पर दिया, चाहे रात हो, दिन हो, बरसात हो या कड़कती धूप हो, वह प्लेयर जब वहां जिन्दगी में घुलता है और अपने खेल में आगे जाने के लिए कड़ी मेहनत करता है तो उस समय किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं होता है ।

सभापति महोदया, अब मैं अमृतसर की बात करना चाहता हूं । अमृतसर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर होने के अलावा, मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी अमृतसर में हुआ करते थे । स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की बात मैंने भी बार-बार पार्लियामेंट में रखी है । कई बार वह बात आगे बढ़ी, लेकिन वह रूक जाती है । पाकिस्तान हमारे बच्चों को खराब करने के लिए कभी नशा बेचता है तो कभी हथियार बेचता है ।

सभापति महोदया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि अमृतसर में रामदास, अजनाला जैसे कई जिले हैं । अमृतसर सिटी का सारा एरिया 20 किलोमीटर की सराउंडिंग में है । आप कहीं भी एक अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम और एक वैलनेस सेंटर खोल सकते हैं । गुरु नानक देव इस मामले में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है । जब भी खेलों की बात होती है तो सबसे ज्यादा ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी लेकर जाती है । इस बार भी वे लेकर गए हैं । आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ही स्पोर्ट्स और वैलनेस सेंटर बना दीजिए । मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी और आपकी देश में मेडल लाने की जो चेष्टा है, उसमें हमारा अमृतसर क्षेत्र सबसे ज्यादा हिस्सा पाएगा । धन्यवाद ।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा): सभापति महोदया, आपने मुझे भारत में क्रीड़ा को बढ़ावा देने के लिए नियम 193 के अधीन चल रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

मैं सतारा, महाराष्ट्र लोक सभा क्षेत्र से आता हूं, जहां कुश्ती का पहला मेडल वर्ष 1952 में खाशाबा जाधव ने जीता था । उसके बाद, 42 साल बाद भी पूरे भारत में किसी को व्यक्तिगत पदक नहीं मिला । यदि भारत में उनके नाम से कुश्ती के खेलों में पुरूष या महिला कोई मेडल जीतकर आती है तो उनके नाम से खाशाबा जाधव पुरस्कार दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा । देहात से आया हुआ एक काश्तकार का बच्चा, जिसने अपनी कमाई और मेहनत से दो आने, चार आने, आठ आने की वर्गणी करके वर्ष 1948 में लंदन भेजा था, लेकिन उनको पदक नहीं मिला । लेकिन, वर्ष 1952 में वे फिर से गए और कांस्य पदक जीतकर आए । यदि खेल मंत्रालय उनके नाम से एक पुरस्कार भारतीय कक्षा में देने की कोई योजना बनाती है तो हम पूरे महाराष्ट्र के लोग और कुश्ती प्रेमी उनके आभारी रहेंगे ।

मैडम, रात का मैराथन अभी परसों पुणे में हुआ है । दिन में शहरों में मैराथन करना उचित नहीं होता है । जब मैं पुणे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था तो उस समय मेरे मित्र सुरेश कलमाड़ी और तब के आदरणीय मुख्य मंत्री शरद पवार जी ने मैराथन के लिए जो सुविधा देकर मैराथन चालू करवाई थी, वह दिन का मैराथन था, लेकिन अब रात का मैराथन हो रहा है । अगर भारत में क्रीड़ा मंत्रालय द्वारा रात के मैराथन के लिए पुणे वालों का जो अनुभव है, उस अनुभव को लेकर खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, तो कई जगहों पर अच्छे साबित होंगे । इसमें जिनको पुरस्कार मिला है, वे इथोपिया के लोग हैं । अगर हमारे देश में भी लोगों को ट्रेनिंग और अच्छी खुराक दी जाए तो वे मैराथन रेस में निश्चित तौर से भाग लेंगे ।

आजकल देहात के बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं । हालांकि जब मैं सिक्किम का राज्यपाल था, वहां के बच्चे अच्छी तरह से फुटबॉल खेलते हैं । चाहे बाईचुंग भूटिया हो या वहां के जो अन्य खिलाड़ी हैं, वे बचपन से ही फुटबॉल खेलते हैं । अगर फुटबॉल के ग्राउंड की सुविधा हो जाए, जो कि एक एकड़ पर बनता है, अगर ग्रामीण इलाकों में यह सुविधा दी जाए, तो बच्चे खेल सकेंगे ।

आजकल हमारे देहातों में तीरंदाजी का प्रचलन काफी चल रहा है । चाहे राम-लक्ष्मण हों या अर्जुन हों, उनकी तीरंदाजी की वजह से लोगों में एक आकर्षण पैदा हुआ है, लेकिन तीरंदाजी पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है । छोटे-छोटे गांवों में जो कोच होते हैं, अगर उनके लिए सेंटर बनाएंगे, तो अच्छा रहेगा । मलखम महाराष्ट्र राज्य की विशेषता है । चाहे लकड़ी का मलखम हो या डोरी का मलखम हो, अगर आप उनके लिए कुछ प्रावधान करें, जो बच्चे और बच्चियां अच्छी तरह से खेल रहे हैं, अगर उनकी तरफ ध्यान देंगे, तो मलखम भी आगे बढ़ेगा ।

अभी बीसीसीआई की बात हुई है । जब आदरणीय शरद पवार जी इसके अध्यक्ष थे, जिसने भी एक टेस्ट मैच खेला है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को पूरी जिंदगी हर महीने 25,000 रुपये सेवाधन या जिसे पेंशन कहते हैं, वह दिया जाता है । आज क्रिकेट के प्रति जो माहौल पैदा हुआ है, वह इसीलिए है, क्योंकि जब वे खेलते हैं, तब भी उनको विज्ञापन से पैसे मिलते हैं और खेलने के बाद भी उनको पैसे मिलते हैं । जब वे रिटायर हो जाते हैं, तब भी उनको 25,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं ।

पुणे में श्री शिव छत्रपति क्रीड़ानगरी बनाई गई है । जब मैं पुणे का जिलाधिकारी था, तब आदरणीय पवार साहब ने 300 एकड़ जमीन दी थी । अभी महाराष्ट्र सरकार वहां एक खेल विश्वविद्यालय बना रही है । पटियाला का जो प्रावधान है, हमारे खिलाड़ी पटियाला जाते हैं, वह काफी दूर है । श्री शिव छत्रपति क्रीड़ानगरी पुणे में है, अगर उसका निदान करें और वहां जाकर देखें, तो वहां 300 एकड़ जमीन है । वहां 30 तरह के स्पोर्ट्स चल सकते हैं ।

वहां भारत सरकार एक टीम भेजे । जैसे अभी मणिपुर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी गई है, वैसे ही दक्षिण में पुणे में मुंबई के पास जगह है और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है । वहां कोच और कुछ राशि देंगे, तो श्री शिव छत्रपति क्रीड़ानगरी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन पाएगी । वहां सभी बच्चों को अच्छी तरह से सुविधा मिल जाएगी । अगर आप वह सुविधा देने की कृपा करेंगे, तो मुझे लगता है कि आज जो विषय लाया गया है, आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Thank you, Madam Chairperson. I was hoping that the Sports Minister would be here, but I can understand his state of mind, especially after what has happened in his home State. So, I am sure that somebody else will take notes on his behalf.

Ours is not a sporting country. Ours is not a sporting society. If you look at a family activity, what do families indulge in as a family activity? They would perhaps go out to eat at a restaurant or they would go to a temple together or they would go watch a movie together or they would go to shop together. We rarely see an entire family playing a sport together. Have you ever seen a mother, father, and two young children actually playing a sport? Sports is really not part of our society. Our educational system, which is based on exams, tuitions, and homework is the greatest impediment for the growth of sports in this country.

I have a very few concrete suggestions, which I hope the Government will take into account. Firstly, there should be no school -- whether private or public or Government -- that can function legally without having a sports ground of its own. This is the first step. We must give access to playing fields. There are so many schools in this country that are in building blocks without playing fields.

Secondly, a physical education teacher should be compulsory in every school, and he must be given the respect that the maths teacher gets or the chemistry teacher gets. In most schools, the physical education teacher is only used to catch late-coming students or to punish students who are in detention.

There is no respect for a physical education teacher. The first step is that the society and the educational system should start respecting physical education teachers.

As we are an exam-oriented society, the only way to make sure that sports is compulsory is to say that if you do not meet certain physical criteria like you cannot run a mile in eight minutes or in six minutes, you cannot write your board exams. If you have to write a board exam and you have to pass the 10th standard board exam or a 12th standard board exam, you must have compulsory physical education as part of your subject and if you do not meet the physical condition, you cannot write the board exam.

Until you make it compulsory in this country, no mother will send their daughters to play. First of all, they will say that they will get dark if they play sports. That is another culture in this country. That is why most of the children are overweight. They do not play sports and they are caught in this burden of exams. The only way is that unless you make sports compulsory and a certain sporting standard has to be met in order to write the board exam, people will never take it seriously.

Madam, I want to tell you something else. Please do not build large stadiums. Building large stadiums is the biggest waste of money. We hardly use stadiums. If you do a proper audit, and you check how many times a stadium is used to its full capacity, you will see that it is very less. Please do not build big stadiums in this country. Please build smaller stadiums that can be dismantled after a sporting event and be moved elsewhere. We do not need large stadiums in this country. Let us also make sure that the existing big stadiums are converted into training centres and sports hospitals. The Government must conduct an audit of all large stadiums and submit a report to this august House.

Please start hiring sportsmen in the Government institutions. Sports recruitment is very, very low. Most sportsmen do not become IPL players and do not get endorsements. They have a playing career and their playing career ends. There is no social security for them. Please start hiring sportsmen in all Government institutions but do not tie them to desk. Hire them through sports quota and encourage them to travel throughout the country to spot talent. In fact, under CSR budget, companies must be encouraged to hire sportsmen but they must not be given desk jobs. They must be told to travel to the districts to spot talent and bring those talents forward.

The main problem is that we do not have access to playing fields. That is where our resources must be spent. We should not be spending on stadiums. We should be spending money on coaches who can go and spot talent.

We also need to encourage international coaches to come to India, pay them market salary so that they find it viable to come and work in India. It is very, very important to have the new technologies which are available in sports. Bring those technologies here.

Madam, two more minutes please. Please give cash incentives to sportsmen based on their ranking. Let there be no arbitrariness in this. Most sports have international ranking. If you achieve a certain ranking, let the Government give a certain incentive at the end of the year, for example, in Tennis or most international sports.

We have to think out of the box. We have to break the vertex of exam, tuition and homework. Start giving respect to physical education teachers. Insist on playing fields and stop building these big stadiums.

Lastly, please in your ego do not bid for the Olympics. It will bankrupt the country and it is not going to do anything. So, in your ego, please do not bid for the Olympics.

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): सभापति महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद । खेल एक ऐसा विषय है, जिसे हर हृदय को समझने की आवश्यकता है । अगर हम अपने बचपन में जाएं तो जिस समय माता-पिता अपने काम में व्यस्त होते थे और बच्चे को एक लाइन बोलते थे कि "बेटा जा खेलकर आजा या बेटी जा खेलकर आजा' तो यह खेल का आदेश मिलना ही उनके हृदय के उल्लास और उमंग को दिखाता था । हमें वहां से शुरू करना है ।

खेल एक ऐसी विधा है, जो हर स्तर के लोगों में, हर गरीब या अमीर व्यक्ति के जीवन स्तर में उमंग लाती है । ऐसा कहते भी हैं कि "स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है और स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ शरीर को ही धारण करती है ।" इन सब परिस्थितियों में आज हमारा देश वर्तमान में दौड़ रहा है । मैं विगत परिस्थितियों में झांककर देखती हूँ कि उस समय गांवों में बेटा या बेटी चाहे गिल्ली-डंडा खेले, चाहे सतोलिया खेले, चाहे स्टापू खेले, चाहे रस्साकसी करें या चाहे उछल-कूद करें, उन खेलों के जरिए उनके शारीरिक स्टेमिना में वृद्धि होती थी ।

मोटा खाना, मोटा पहनना, मोटा खेलना, मोटा दौड़ना आदि ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं । मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि वर्ष 2018 में 'खेलो इंडिया' की कल्पना की गई । इस कल्पना के पीछे अपने देश की युवा शक्ति को ऊपर उठाना था और युवा शक्ति केवल शहरों में निवास नहीं करती । देश में 80 प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं और गांवों के अंदर निवास करने वाले हमारे युवा, हमारे नौनिहाल वाकई इन प्रतिभाओं के धनी हैं । आज 'खेलो इंडिया' के तहत जब हमने सांसद खेल प्रतियोगताएं आयोजित कीं, तो बेटे और बेटियों में बराबर उत्साह था और इतना उत्साह था कि वे अपनी-अपनी प्रतिभा को वहां प्रदर्शित करके अपना एक स्थान बनाना चाहते थे । सबसे बड़ी दिक्कत वाली जो बात है, वह है हमारा ट्रेनिंग सिस्टम । विभिन्न प्रकार के खेलों को उस नियोजित ढंग से और अनुशासन में रहते हुए किस प्रकार हम खेलाना चाहते हैं, ये बातें विचार करना बहुत जरूरी हैं । 'खेलो इंडिया' के अंतर्गत पूरे देश के अंदर राज्यों ने भी खेलों का आयोजन किया, भले ही राजस्थान ने नाम बदलकर खेलों का आयोजन किया, लेकिन किया और इसलिए किया, क्योंकि भारत सरकार ने अकेले राजस्थान को ही 48 योजनाएं दीं और उनमें 112.28 करोड़ रुपये राशि भी दी । दुर्भाग्यपूर्ण यह होता है कि राजनीतिक उठापटक में हमारी प्रतिभाओं को जिस तरह से तराशना चाहिए, उस तरह से तराशा नहीं जाता है और दिमाग में जो वोट की पॉलिटिक्स होती है, वह हमारी युवा शक्ति और हमारे विद्यार्थियों की प्रगति में बाधक बनती है । नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थी शिक्षा नीति के केन्द्र में है । उसकी आत्मनिर्भरता, उसका स्वावलम्बन आदि हमारे लक्ष्य हैं । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नि:सन्देह खेल एक ऐसी विधा है, जिसे हमें तराशना होगा, संवारना होगा, परखना होगा और देहात में उसे चिन्हित करना होगा । मैं ग्राम पंचायत स्तर की बात करना चाहूंगी और माननीय खेल मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि ग्राम पंचायत तीन-चार या पांच गांवों का एक संकुल होती है ।

वहां खेल की पूर्ण सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि हमारे छोटे बच्चे, हमारे दूरस्थ और दुर्गम स्थानों में रहने वाले, कठोर परिश्रम में जीने वाले बालक-बालिकाओं को खेल का लाभ मिल सके । मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगी कि खेल एक ऐसा जीता जागता, सामर्थ्य प्रदान करने वाला उपक्रम है, जिसे हमें संभालना है । आज़ादी के बाद विगत 75 वर्षों में हमारा अधिकांश समय केवल नगरीय व्यवस्थाओं की वृद्धि करने में, औद्योगिक क्षेत्र में नौकरियां देने में और हमारे बच्चों को पलायन करने के लिए मजबूर करने में ही निकला है । इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन मैं इस बात को मानती हूं, क्योंकि मैं गांव की एक महिला हूं, गांव में पली-बढ़ी हूं और गांव में सितोलिया और स्टेपो खेलकर अपने स्टैमिना को बढ़ाया और आगे बढ़ी हूं । आज 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने जो कार्यक्रम स्वीकार किए हैं, खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित कार्यक्रम के क्रियान्वयन को जो मंजूरी दी है, यह मंजूरी हमारे

धरातल तक पहुंचनी चाहिए। यह केवल टॉप लेवल पर, बड़ी-बड़ी जगहों पर स्टेडियम बनाने से सिद्ध नहीं होगी। आज क्रिकेट का खेल, जिसमें खेल खेलने वाले हमारे 11 या 22 भाई होंगे, लेकिन उसे देखने में पूरा देश समय बर्बाद करता है। जब खेल हमारी ग्राम पंचायत में होता है, तब वहां ग्राम पंचायत के लोग, जिनको टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, वे उस खेल को अपनी आखों से देखते हैं, तो वे अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि खेलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी, यदि हम देश के युवा को, नौजवान को, देश के बेटे और बेटी को समान रूप से पुष्ट करना चाहते हैं तो हमें सुविधाओं का विस्तार करना पड़ेगा। आज युवा शक्ति खेलों के प्रति बहुत उत्साहित है, उस उत्साह के साथ हमारा एक परम लक्ष्य है कि जहां खेल खेले जाते हैं, वहां मैत्री होती है।

वहां आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। जो खेल खेलने वाले, हारने-जीतने वाले होते हैं, उनमें हारने वाला अपने प्रयास को और अधिक दुरुस्त करने की सोचता है तथा जीतने वाला अहंकार में नहीं आता है। ये संस्कार कौन देगा? यह कोच देते हैं, हमारे ट्रेनर देते हैं और प्रशिक्षण देने वाले हमारे शिक्षक देते हैं। उनके अंदर दुर्भावनाएं न हों, मोरली साउण्ड हों, तभी हमारी बेटियां खेल के लिए आगे आएंगी।

माननीय सभापति : अब आपकी बात पूरी हो गई है। आप बैठ जाइए।

श्रीमती जसकौर मीना : महोदया, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि भार उठाने वाली बेटी केवल घास खोदकर और लकड़ियां बीनकर आगे बढ़ रही थी, उस मीराबाई ने गोल्ड मेडल जीता है। उसने किस तरह से अपने आपको भार उठाने में सक्षम किया और उसके लिए कोई ट्रेनर भी नहीं था। उसकी जीवनशैली ही ऐसी थी कि पहाड़ों से घास लाना और पहाड़ों पर जाकर लकड़ियां उठाना। जब वह यह काम करती थी तो उसे भार उठाने की आदत पड़ गई। मैं भी आज कहूं कि मैं दो मटकी अपने सिर पर खुद रख लेती थी। यह कैसे रखती थी? आज शहर का बच्चा नहीं रख सकता है, क्योंकि स्टैमिना नहीं है। जो पढ़ाई का सिस्टम है, वह सिस्टम एक रटन्तू तोते की तरह है। किताबों को रटकर प्राप्त किए ज्ञान को पुस्तक में उड़ेल दिया, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। जब तक प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा, तब तक नहीं होगा और यह तभी होगा, जब खेलों के माध्यम से हम बच्चों को पूर्ण समय देंगे।

मुझे विश्वास है कि 'नई शिक्षा नीति' के अंतर्गत खेलों के बारे में काफी कुछ सही प्रेजेंटेशन किया गया है। यह सही है कि पहला सुख निरोगी काया। यह निरोगी काया कैसे रहेगी? यह पिज्जा, बर्गर खाने से नहीं रहेगी, टीवी के आगे बैठे रहने से नहीं होगी और मोबाइल पर गेम खेलने से भी नहीं होगी, बल्कि उसको मैदान में उतारना पड़ेगा। मैदान में उतारकर हम उन बच्चों को सशक्त और मजबूत करेंगे, क्योंकि युवा शक्ति खेलों की तरफ मोहित हो चुकी है। विगत वर्ष 2018 से अब तक खेलों के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, नि:संदेह सराहनीय हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान आदि जैसे केन्द्रों ने भी बेटियों को खेलों के अंदर उतारने की कोशिश की है। आज राजस्थान के अंदर मोदी इंस्टीट्यूट, जहां लगभग तीन हजार बेटियां पढ़ रही हैं। मैंने खुद वहां जाकर देखा कि वहां पर खेलों के लिए प्राथमिकता है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि मैं खुद भी तीस साल से एक संस्था की संचालक हूं, जिसमें केवल अनुसूचित जनजाति की बेटियों को तरासते हैं। जब उन बेटियों को कबड्डी में देखते हैं तो वे बेटियां शहरों के मुकाबले कहीं अधिक स्टैमिना लेकर आगे बढ़ती हैं।

महोदया, आपने मुझे समय दिया, लेकिन मैं एक सलाह जरूर देना चाहूंगी कि जो खिलाड़ी जिला स्तर पर खेलता है, प्रदेश स्तर पर खेलता है, राष्ट्रीय स्तर पर खेलता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है, उस खिलाड़ी को कोई पहचान पत्र दिया जाए। यदि वे कहीं जॉब के लिए जाएं तो कोई मार्किंग ऐसी हो कि हम उन बच्चों की पहचान के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर उन्हें कहीं नौकरियों और अन्य जगहों पर भी सुगमता देंगे। ये मेरे सुझाव हैं। मेरे सुझाव तो बहुत थे, क्योंकि मैं सब कुछ प्रैक्टिकली देखती और करती हूं। मेरे सुझाव तो बहुत थे, लेकिन महोदया आप बार-बार रोक रही हैं तो मैंने यह सोच लिया कि मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर दूं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह बहुत अच्छी बात है। सबको समय देना है।

श्रीमती जसकौर मीना : मैं फिर कहूंगी कि खेलों में खेलने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई स्पेशल कोटा होना चाहिए, कोच प्रशिक्षित और मोरली साउण्ड होने चाहिए, महिला कोच भी अधिक से अधिक लगानी चाहिए, तभी हमारी बेटियां आगे आएंगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Thank you, Madam Chairperson. Being a youth representative, I would request a few more minutes. I take this opportunity to raise the issue regarding fate of sports in our country. Firstly, we need to understand what is plaguing sports in our country. I can deliberately say that nepotism and group politics have been completely ruining the sports industry in our country. I would like to know from the Sports Minister, through you, whether we have world-class infrastructure or world-class trainers. How can we expect medals specially when we think about Olympics? Can India ever dream of being number one in Olympics? Forget about achieving it, can India at least dream of it? Has India dreamt of it? Of course, I do understand that we have improved a lot in recent times. In the last Olympics, perhaps we have won seven medals. But we need to take revolutionary measures in terms of improving sports in our country.

I would like to give a fair example of the great Indian epic Mahabharat. Once Guru Dronacharya took Pandavas and Kauravas to the forest. He placed one wooden bird on the top of the tree and asked Dharmaraj to aim at the bird's eye with a bow and arrow. Dronacharya asked him what he could see. Dharmaraj told him that he could see the bird. Dronacharya again asked the same question, to which he replied saying that he could see trees, flowers, and everything. The Guru asked him to release the arrow and Dharmaraj failed to hit the target. At a later stage Duryodhan came and the same thing was repeated. Eventually, Arjuna came and aimed at the bird. When Dronacharya asked him what he could see, he replied that he could see the eye of the bird. The Guru again asked him, what else he could see, to which he again replied that he could see only the eye. Dronacharya asked him to release the arrow, and Arjuna was able to hit the target. What is the moral of the story? The moral of the story is that it requires pure dedication, determination, and concentration to achieve the target. Likewise, the Government should take proactive measures to achieve the goal of being a global super power in sports. Population-wise India is the second largest country in the world. We are the fifth or the sixth largest economy in the world. Area-wise, we are the seventh largest country. But when it comes to sports, we are hovering around about 48th or 50th rank. We need to be very aggressive. If India really wishes to be a global super power in the world, definitely revolutionary measures need to be taken.

I would like to quote hon. Member, Hema Malini ji who raised an interesting question in this House. In the Question Hour she had asked the Minister, 'Does the Government have any plan to set up and encourage a dedicated sport which is famous in the respective States'. For example, football is famous in Bengal and hockey is famous in Punjab. Likewise, badminton is famous in Andhra Pradesh. If the Government can encourage a sport which is famous in a State, the sports lovers will frequently travel to that particular State. In a way, the tourism sector will also be complemented. There will be a lot of cultural exchanges, and in a way, the revenue in the form of different avenues like the advertisement, branding, will improve. I would like to give one more example of Michael Phelps. The entire House, rather the whole world, must be knowing about him. He is the most decorated Olympian in the history of Olympics. He bagged 28 medals in Olympics, out of which 23 are Gold. Can any Indian ever dream of it? It has not happened just because of his practising hard. It needs a lot of sacrifice, dedication, commitment, and meticulous planning. I read in a book that he used to spend half of his day in water. It is not that easy. I would like to ask the hon. Minister, through you, Madam, how many temperature-controlled swimming pools do we have in our country.

How many world-class or Olympic-standard swimming pools do we have? If we count such swimming pools on finger tips, we will find that they are hardly one or two or three. How can swimmers practice in winter and monsoon seasons? How can we expect wonders to happen? It cannot happen. Madam Chairperson, in the water sports division, there are more than sixty medals in the Olympics. … (Interruptions) Madam, please give me one more minute. … (Interruptions)

माननीय सभापति : मैंने आपको पहले ही छ: मिनट दे दिया है।

श्री मारगनी भरत: मैडम, कृपया एक मिनट का समय दे दीजिए।

माननीय सभापति : ठीक है।

*m20 SHRI MARGANI BHARAT: Madam, at the Olympic Games, in the water sports division, there are more than sixty medals. There are about 180 medals comprising of gold, silver, and bronze medals. So, how many medals India can achieve if we do not have a world-class infrastructure?

Madam, whenever we ask a question related to sports to the Government, the Government deliberately says that 'sports' is a State subject. Then, is it not the pride of our country? … (Interruptions)

माननीय सभापति : अब आप बैठ जाइए।

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि जी।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Thank you, Madam Chairperson.

Madam Chairperson, I completely agree with most of the speakers who have spoken before me and who have insisted that sports should be made a part of our education system and should be made mandatory. Today, we have seen that many of the schools, and especially private institutions, do not have any space for children to play. We see advertisements that the classrooms have air conditioners but there is no place for the children to come out and play. If children do not learn team spirit and if they are not allowed to play, how will they have a healthy life? How will they understand the importance of being together? Maybe, 'being together' is not a good word in these days. But I think, 'team spirit' and 'people coming together beyond differences' are the most important things. We have to teach our children in this regard.

We keep talking about our strength that India lives in villages or in rural areas. But do we encourage sports among children living in these areas? Do we reach children in rural areas and villages? Do we support and help them? In my constituency, especially in a place called Kovilpatti, children love playing hockey. How many of them can afford to buy hockey sticks? How many of them can even afford to buy shoes? How many of them can even afford to buy clothes? How do we reach these children? How do we support them? We do not have hockey turfs in most of the places. The children, who want to run, have no tracks to run. How do they practice? What will happen to their dreams? How will they get the same opportunities that children in cities and in developed nations get?

The Government of India provides sports equipment to schools under the Fit India Movement and Samagra Shiksha Abhiyan. But sadly, some schools avail benefits from both the schemes and some schools are completely ignored and they do not get anything. I would like to know what kind of accountability is there to make sure that schools are not ignored. Most of the top sports associations in this country are ridden with politics, interference by politicians, power games, and corruption. Many of the hon. Members have mentioned that they are the bureaucrats and politicians who control these associations. They are the ones who actually have the final say in the lives of sportspersons.

They decide who has to be selected and who has got talent. It is not going to be unbiased. So, how are we going to make sure that there is justice?

The hon. Member, Shri Margani Bharat, who spoke before me, talked about Dronacharya. I would like to talk about another story in Dronacharya's life. It is about Eklavya. Eklavya belonged to a lower caste. He belonged to a Scheduled Tribe community.

He was such a good archer. He was better than Arjuna. As he comes from a Scheduled Tribe community, he was deprived of that. He was made to cut his thumb finger. The great Dronacharya wanted the thumb finger of his student as dakshina. This sort of caste politics has not gone away. This caste oppression is still there in sports today. How many children from Dalit community and how many women from that community get opportunity to play? In a

village, where people cannot touch each other, where people cannot walk in the same street, how will these children be allowed to play in teams? They will not be allowed.

You know there are many games where teams have to be formed like kabaddi or hockey. They are not allowed to play. What are we going to do to reach to these people? How will you ensure that these people get justice? I am not saying that you will have to bring in reservation in sports also. But at least you must do something to protect these people to ensure them the justice particularly to children and women. You know very well the struggle women have to face to get into sports. It is not easy to convince their families. When they come into sports, we all know the kind of sexual abuse which they face. How are we going to protect these women who come into sports? What kind of importance do we give to Paralympics? Nobody talks about it. Nobody cares about that. I think the people who are differently abled have the same right as everybody else to express their talent. Transgenders, who are not men or women, also have no space in sports.

I think sports has moved on. We have to have science and activity together. Somebody has to monitor their talents and weaknesses. Many sports athletes get injured. As they do not have access to medical facilities, their career comes to an end. How are we going to support these people?

I know this Government does not approve of high protein diet in many cases. But sports people need high protein diet. We have to ensure that. So, we have to understand about the diet, science and everything has to be taken into consideration if we really want more people come into sports. More young people need to be encouraged to come in sports.

I would also like to ask one thing about swimmers. How many people or swimmers are encouraged from coastal areas to get into swimming? No swimmer comes from coastal areas. They are born to swim. We do not encourage them. We have to consider all these things.

Thank you, Madam.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : माननीय सभापति महोदया, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे खेल के विषय पर बोलने का मौका दिया ।

सभापति महोदया, हम आज ही खेल नहीं खेल रहे हैं, पूर्व जमाने से ही हम खेल खेल रहे हैं । भगवान श्रीकृष्ण ने भी खेल खेला था । अपनी गेंद को जमुना में उछालकर कालिया नाथ को नाथने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने खेल खेला था । भगवान राम ने भी 14 वर्षों तक वनवास का खेल खेला था, रावण और राक्षसों के नाश का खेल खेला था । राक्षस मुक्त समाज बनाने का उन्होंने खेल खेला था । आज भी खेल हो रहे हैं ।

सभापति महोदया, मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा । उन्होंने 'खेलो इंडिया' के माध्यम से देश में खेल का एक वातावरण बनाया और खेलों को प्रोत्साहित करने का काम किया । जब हमारे खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं, जब वे चयनित होते हैं, तो हमारे खेल मंत्री स्वयं उनसे मिलने जाते हैं । लौटने के बाद और जाने से पहले प्रधान मंत्री जी खिलाड़ियों से मिलते हैं ।

17.00hrs

महोदया, खेल के मैदान में जाने से पहले दूरभाष पर भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी करते हैं । देश में खेल का बजट बढ़ाया गया है, उससे खिलाड़ी उत्साहित हैं और यह देश में खेलों को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है । खिलाड़ी गोल्ड मैडल जीत रहे हैं । हम आंकड़े देखें चाहे ओलम्पिक खेल हों, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमन वैल्थ गेम्स हों, वर्ष 2014 से पहले और बाद के मैडल्स की संख्या में बहुत अंतर है । मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से भारत खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में किसी भी खेल में भारत का खिलाड़ी निश्चित रूप से गोल्ड मैडल ही हासिल करेगा । मैं यह कहने में संकोच नहीं करता हूं कि भारत के खिलाड़ी केवल अपना या अपने राज्य का सम्मान ही नहीं, बल्कि देश का सम्मान बढ़ाने में कामयाब होंगे ।

महोदया, खेल मानव जीवन को भी जीवंत बनाता है । खेल केवल नौजवान या युवाओं के लिए ही नहीं है । खेल बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, वृद्धजनों के लिए भी है, महिला बहनों के लिए भी है और दिव्यांगजनों के लिए भी है । दिव्यांग भाई, बहन भी चाहे भारत में खेल हों या विश्व स्तर के खेल हों, वे गोल्ड मैडल लेकर देश का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं । यह कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जिस तरह से खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, हम गांव के गली-गलियारे के खिलाड़ियों को चिह्नित करके सबके सामने लाने का जो काम कर रहे हैं, उसमें हम और ज्यादा कामयाब होंगे ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकारें भी खेल खेलती हैं । पहले की सरकार खेल खेलती थी, लेकिन वह घोटाले के खेल खेलती थी । आज की भी सरकार खेल को खेल रही है लेकिन जन कल्याणकारी योजनाओं का, विकास का, महिलाओं को आगे ले जाने का, किसानों के कल्याण का, वृद्धजनों के ध्यान का खेल आज की सरकार मिशन मोड में खेलने का कर रही है ।

आज देश के विकास का खेल चल रहा है और एक तरफ 'भारत जोड़ो' के नाटक का भी खेल चल रहा है लेकिन हमारे देश के प्रधान मंत्री देश की समस्याओं के मिशन पर खेल खेल रहे हैं, देश की समस्याओं का निदान कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा, देश विकास के रास्ते पर कैसे आगे जाएगा, यह खेल हमारे देश के प्रधान मंत्री और देश के खेल मंत्री खेल रहे हैं । यह जीवन भी एक खेल है और हमें जीवन में सफलता से खेलने की आवश्यकता है और जिस तरह से सरकार खेल रही है, यह देश के 130 करोड़ लोगों के जीवन की सफलता के लिए, इस देश की सफलता और उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए बहुत अच्छा संदेश है । जिस तरह से देश के विकास की कहानियों को हम इतिहास के पन्नों में दर्ज करते जा रहे हैं, हमें लगता है कि देशवासियों को इस पर गर्व है और हम इसके लिए देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को हृदय से बधाई देते हैं । मैं देश के खेल मंत्री को भी बधाई देता हूं कि वे लगातार खिलाड़ियों के लिए प्रयास कर रहे हैं ।

महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विद्यालय स्तर से भी चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, खेल का बड़ा वातावरण होता था, खेल का मैदान होता था । हम लोगों के जमाने में ऐसा होता था, लेकिन शायद अब यह खत्म होता जा रहा है । खेल राज्य का विषय है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप केंद्र से एक दिशा-निर्देश राज्यों को भी दें कि इस विषय को जीवंत करें । जिला या राज्य स्तर से खिलाड़ी चयनित होंगे, तो मुझे लगता है कि खेलों का ज्यादा महत्व मिलेगा और इसका लाभ ज्यादा मिलेगा । पंचायत स्तर पर भी यहां से कोई गाइड लाइन माननीय मंत्री जी दें कि जो पुराने खेल खत्म होते जा रहे हैं, जैसे गुल्ली डंडे का खेल है, कुश्ती के अलावा कबड्डी, हाथ की ताकत अजमाने का खेल चलता था, ऐसे खेलों से एक वातावरण बनता था । चूंकि हमारी सरकार हर खेल को जीवंत कर रही है, यदि इन पुराने खेलों को जीवंत करने का काम करें तो अच्छा होगा । भारत का दुनिया में परचम लहलहा रहा है

और जी-20 की अध्यक्षता करने का भारत को मौका मिला है, इसके लिए भी मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं। मैं खेल मंत्री जी को भी बधाई देते हुए आग्रह करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, उन्हें आप स्वीकार करें। धन्यवाद।

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): सभापति महोदया, मैं खेल के विषय पर बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

हमारे देश के जो खिलाड़ी मेडल्स जीतते हैं, सरकार उनको सम्मान देती है और प्रधान मंत्री जी उनसे फोन पर बात करते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन कराटे का खेल हमारे देश में ऐसा खेल है, जो ओलम्पिक में भी इनक्लूड हुआ। यह खेल जो खिलाड़ी खेलते हैं, उनका सम्मान करना तो दूर की बात है, प्रधान मंत्री जी के फोन की तो दूर की बात है, खेल मंत्री या खेल राज्य मंत्री जी का भी फोन नहीं आता है और न ही उन्हें सरकार से कोई बेनिफिट मिलता है।

इसी साल जकार्ता में कराटे की चैंपियनशिप हुई। उसमें दिल्ली के कुणाल शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन किसी ने बधाई देने के लिए उसे फोन नहीं किया। मेरे जिला बारपेटा के निशाद अली ने वर्ष 2018 में डरबन में हुई कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, लेकिन किसी ने बधाई के लिए फोन नहीं किया और न ही सरकार से एक पैसे का अनुदान मिला। केवल यही नहीं, 10th कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में दोबारा निशाद ने बर्मिंघम में ब्रॉंज मेडल जीता, तब भी किसी ने उन्हें फोन नहीं किया। असम के ही हेम्फू बोंगजांग को 9th कॉमनवेल्थ कराटे में स्वर्ण मिला था, जो डरबन में हुआ था। इस साल थाईलैंड में उसे गोल्ड के साथ ब्रॉंज मेडल भी मिला, लेकिन किसी ने फोन करके बधाई नहीं दी और न ही आर्थिक अनुदान मिला।

महोदया, केवल यही नहीं, मेरे जिले के वसीम अली को भी मेडल मिला, लेकिन किसी ने फोन करके बधाई नहीं दी और न ही आर्थिक अनुदान मिला। सदन में इस समय खेल मंत्री एवं खेल राज्य मंत्री मौजूद हैं। दोनों से मैं गुजारिश करता हूं कि कराटे को भी हमें प्रमोट करना चाहिए। पहले श्री किरेन रिजीजू जी खेल मंत्री थे। मैंने उनसे भी अनुरोध किया था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के काफी बच्चों ने इंटरनेशनल कराटे इवेंट्स में मेडल्स जीते। अत: कराटे को भी हमें प्रमोट करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सरकार अच्छी तरह से इसका प्रमोशन करेगी, तो हमारे टैलेंटेड कराटे प्लेयर्स देश के लिए ओलंपिक हासिल कर सकते हैं।

सभापति महोदया, सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है। मैं सोचता हूं कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए खेल एक उत्तम माध्यम हो सकता है। अत: खेल को हमें प्रमोट करना चाहिए। खेल राज्य मंत्री कूचबिहार से हैं और मेरा क्षेत्र ग्रामीण इलाका है, अत: मैं बताना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में, चाहे पूर्वोत्तर भारत हो या उत्तर भारत हो, वहां के बच्चे नदी में भी स्विमिंग सीखते हैं, लेकिन स्विमिंग के लिए जो वातावरण हमें क्रिएट करना चाहिए, वह हम कर नहीं पाए हैं। सिटी, टाउन एवं अर्बन एरिया में स्विमिंग के लिए अनुकूल वातावरण है, वह अच्छी बात है, लेकिन मैं खेल मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि ग्रामीण इलाकों में भी स्विमिंग के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए।

मेरे जिला बारपेटा में रामराय स्टेडियम के विकास के लिए मैंने सरकार से काफी निवेदन किया, लेकिन अभी तक उसका विकास नहीं हुआ है। मैं खेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि रामराय स्टेडियम का विकास होना चाहिए। मेरा एक निवेदन यह भी है कि मेरे क्षेत्र के बंगाईगांव जिला के सब डिवीजन किर्तान्पारा में एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए। यह एक ग्रामीण इलाका है।

मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सीग्रीवाल साहब ने 'भारत जोड़ो' मुहिम को अनसुना किया। यह देश के कोने-कोने की संस्कृति को साथ में ले रहा है और कोने-कोने के जितने भी ट्रेडीशनल खेल हैं, उनको भी आगे ला रहा है। राहुल जी अच्छा काम कर रहे हैं। सीग्रीवाल जी आलोचना करेंगे, यह अलग बात है। सरकार को मद्रास से भी एलर्जी है, लेकिन मैं केंद्र सरकार तथा बीजेपी की जहां-जहां राज्य सरकारें हैं, उनसे यह गुजारिश करता हूं कि अगर आप राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मद्रास मेन स्ट्रीम में नहीं है, तो वहां के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप स्पेशल टूर्नामेंट आयोजित कीजिए, ताकि वे लोग भी खेल में आगे आएं और देश की मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सकें।

सभापति महोदया, केंद्र हमारा जो ट्रेडीशनल खेल 'हु तू तू' है और मुझे लगता है कि जो नॉर्थ बंगाल में भी है, उसका भी प्रमोशन करना चाहिए। जितने भी ट्रेडीशनल खेल हैं, उन सभी को प्रमोशन मिलना चाहिए।

महोदया, हमारे केरल के एक साथी ने फुटबॉल के बारे में बोला था। अभी कतर में फुटबॉल विश्व कप हो रहा है। हमारा बहुत बड़ा देश है। हमें तब गर्व होगा जब इस फुटबॉल विश्व कप में हम सिर्फ दाखिल ही नहीं होंगे, बल्कि जब हम लोग इसे जीत सकेंगे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। क्रिकेट में हम लोग आगे हैं, वह ठीक है, लेकिन फुटबॉल में भी हमें आगे जाना होगा। हर पार्लियामेन्टरी क्षेत्र में एक-एक फुटबॉल एकेडमी होनी चाहिए। वुमेन फुटबॉल एकेडमी भी होनी चाहिए।

महोदया, मैं आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। वुमेन फुटबॉल एकेडमी भी होनी चाहिए। महोदया, आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति की अध्यक्ष भी हैं। जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों के खेल के लिए भी प्रमोशन होना चाहिए। उनके लिए भी खेल का वातावरण होना चाहिए। महिलाओं के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि सिर्फ महिलाओं के बारे में बोलने से कुछ नहीं होगा। हिमा दास पहले फुटबॉल की खिलाड़ी थी। हिमा दास की सरकार ने भी बहुत मदद की। वह एथलीट बन गई है। पहले वह फुटबॉल में थी, लेकिन फुटबॉल का वातावरण नहीं था तो वह एथलेटिक्स में आ गई। इसलिए मेरा कहना है कि फुटबॉल का अच्छा वातावरण होना चाहिए, फुटबॉल के लिए अच्छा परिवेश होना चाहिए। यह निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Madam Chairperson, for allowing me to speak on the development and promotion of sports in India.

Madam, this is the right time when we are discussing about sports in India, especially in the light of ongoing football World Cup in Qatar. We have seen that the countries which are having less than 40 lakhs of people have participated in the World Cup football. But it is quite unfortunate to note that a country having more than 130 crores of population is not able to even qualify in the international sports events. This shows the pathetic situation of the sports scenario in our country.

Why is it so? This year, we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of our Independence. We have been able to progress in almost all the fields, in health, education, economy etc. In all the fields, we are having the international standards. But it is quite unfortunate to note that even after 75 years of our Independence, we are not able to have the international standards in sports except in cricket.

You know that we had been the world champion in Hockey for almost 20 years continuously. But now, what is our position in Hockey in international standards, which was one of the most prestigious games in India? Why is it so? The Government has to have an introspection on this. According to me, if the Government have a political will, definitely, the situation can be improved.

In Qatar World Cup football, several small countries have participated. Yes, they have the money. But we can also do it if we have a political will and a sincere attempt on the part of the Government. I would like to urge upon the hon. Prime Minister to take the initiative to have a deliberate attempt to build up the sports personalities in our country. For this, money has to be spent.

Hon. Minister, Shri Anurag Singh Thakur is here. According to his reply in Rajya Sabha, for the last five years, the total money which we have spent for the development of sports is just Rs.11,482.77 crore. We are a 3.5 trillion economy. What is the money being spent for the sports? It is a very negligible amount. This is the reason why we are not able to go up to the international standards.

After Independence, no Government has been sincere and dedicated for the promotion of sports because it does not make any influence on the electorate. It does not gain any political point on electoral politics. That is the reason why we are not able to make any progress in sports.

So, my point is that the Government of India and the hon. Prime Minister should come out with a clear programme to develop sports in our country. There should be a deliberate attempt on the part of the Government. That is the first suggestion which I would like to make.

Madam, we are taking about the funding of sports and the development of sports infrastructure. We should have a better sports scenario in our country. If we train the school children from the grassroot level, definitely, we can minimise the medical expenditure also. We are spending a huge amount of money on medical care and treatment. But if we can build up the sports culture in our country in a big way, we would definitely be able to build a healthy nation thereby minimising the expenditure on the medical field as well.

Madam, what are the issues concerning the sports sector? The first is the identification of talented sportspersons from the rural areas as well as from urban areas. Here, I would like to cite one example of P.T. Usha. Now, she is the President of the Indian Olympic Association, and also an hon. Member of Rajya Sabha. I would appreciate the Government for nominating her in Rajya Sabha. She had practised in the coastal area. One coach, Mr. O.M. Nambiar had found her talent, efficiency, and sporting sprit, and that is the only reason why she could come to play at the international level. She had won many medals in the Asian Games.

So, for identification of talented sportspersons at the grass-root level, the scrutiny has to be done. It may also be done at the school level. It should be on the basis of a specific level.

About modern infrastructure, I need not say that lack of proper modern infrastructure is one of the reasons due to which we are not able to have an international standard of sports.

Here, I would like to draw the attention of the hon. Minister. We had organised the 9th Asiad in 1982, and subsequently we also organised the Commonwealth Games. Then, the last National Games were held in my State of Kerala. You could see the infrastructure that we had built by spending crores of rupees. But what is the state of affairs of that sports infrastructure now? We are not maintaining that infrastructure which we had already built for the games. So, this issue needs to be looked into. Now, I would talk about coaching and expertise. Foreign coaches, who are experts, have to be brought here for giving proper coaching to our sportspersons. Not only this, the financial security and safety of the sportspersons have also to be kept intact. Otherwise, it would be a very difficult situation. Another point, which I would like to make is this. Undue and unwarranted political influence and interference in the sports scenario need to be stopped. My last point is regarding the Corporate and Social Responsibility (CSR) Fund. I am only making points, and not explaining everything. There is a specific provision about Corporate Social Responsibility. Two per cent of the funds have to be given under CSR. We also have a National Sports Development Fund. My point is, why the corporates are not contributing for the development and promotion of sports. I am having the statistics with me. If we examine it, we would know that the contribution in the NSDF by the Corporate Social Responsibility is very less. It needs to be increased. Madam, I support the 'Khelo India Programme' and 'Target Olympic Podium Scheme'. While supporting them, I would like to seek a clarification form the hon. Minister. What about the 'Target Olympic Podium Scheme'?

माननीय सभापति: क्या-क्या खेल खेले हैं, उसके बारे में तो आपने बोला ही नहीं है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I would like to know from the hon. Minister as to what is the result and impact of the 'Target Olympic Podium Scheme'. Similarly, what is the result and impact of 'Khelo India'?

Once again, I would urge upon the Government to come up with a political will to have a better sports scenario in our country.

With these words, I conclude my speech. Thank you very much.

माननीय सभापति : श्री एम. सेल्वराज, क्या आप तमिल में बोलना चाहते हैं?

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Yes, Madam.

HON. CHAIRPERSON: Okay.

SHRI M. SELVARAJ: Madam Chairperson, thank you for this opportunity to take part in an important discussion on the need to promote sports in the country.

Many MPs have given their valuable suggestions. I want to express my suggestions as well. Particularly, Shri Karti P. Chidambaram and Smt. Kanimozhi have given very valuable suggestions. India is a vast country having a population of more than 130 Crores. We need to concentrate more on promotion of sports in order to make our country much stronger. The youth of this country should have a clear and strong mind besides good health so as to make our country a stronger one. Sports can only make this happen. It is only through this sector we can strengthen our young minds with clarity of thought. I welcome the most important "Khelo India" programme, aimed to promote sports in the country. It is a very special scheme.

Many MPs have opined that allocation of funds to the Sports Ministry should be increased. I also join all the Members in urging the hon. Minister to enhance the allocation of funds for the Sports Ministry. Kabaddi is the National game of our country. How much importance does this Government give to the national game 'Kabaddi'? It remains a question mark. Villages are so important. Mahatma Gandhi spoke about Gram Swaraj. We have to identify the talented sportspersons in the rural areas. The Government should take forward the process of identification of such talented sportspersons. Talent hunt is need of the hour.Thousands of youth of our country get training in sports without even having proper spots uniform or shoes to wear or a healthy diet. Have we addressed this problem? The Government should look into this. We watch only cricket on our television sets. Cricket is a good game. At the same time, I wish to say that we should give priority to promotion of various other sports in the country.

Hon. Member Smt. Kanimozhi mentioned here that there is so much of politics in sports. Even factors like religion and caste do harm to sports. Hon. Member Smt. Kanimozhi narrated the story of Dronacharya and the sacrifice made by Eklavya by offering his thumb as Guru Dakshina. This is called untouchability. We should know how this untouchability has affected sports. I want to request the hon. Minister to clarify how many Dalit sportspersons are there in our country? Hon. MP Smt. Kanimozhi has also asked the same question. How many Dalit sportspersons are playing cricket? We talk about equality and social justice in our country. But how many sports are being played by persons belonging to all the communities. We should develop such a culture. Only then, our country can develop and compete with the world nations in the sports arena.

Many Members mentioned about Qatar. Qatar is a small country. But it has carved a niche in the field of sports. But our nation with a population 133 Crores is placed at 50th position. It is a matter of pain and concern. Sports should be included in our curriculum from primary level to college level as a mandatory clause. Moreover, we should not only identify the talented sportspersons from rural areas, but also nurture them in various sports. Only then, we can create more number of sportspersons in various sports like kabbadi, hockey and basketball.

I once again convey my sincere thanks to the hon. Minister for Sports, and Madam Chairperson for allowing me to take part in this important discussion and express my valuable suggestions. Thank you.

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): सभापति महोदया, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । सबसे पहले तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब प्रश्न काल में स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न उठे, तब उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम लोग नियम-193 के तहत चर्चा करेंगे । साथ-साथ मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद है, हमारे दोनों युवा मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं । जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है, मुझे लगता है कि तब से बहुत ज्यादा तरक्की हुई है । वैसे तो आदरणीय किरण रिजीजू जी भी जब मंत्री थे, तब उन्होंने भी बहुत ज्यादा इसमें काम किया था, लेकिन इनके आने के बाद से इसमें और ज्यादा तरक्की हो रही है ।

माननीय सभापति जी, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं हमारी राज्य सभा सांसद पिलावुल्लाकन्डी थेक्केपराम्बिल उषा जी से, जिन्हें हम पी.टी. उषा बोलते हैं । जब मैं कॉलेज में थी तो उस समय मैं स्पोर्ट्स में काफी पार्टीसिपेट करती थी और अपने कॉलेज की लगातार तीन सालों तक 'बेस्ट एथलीट' रही । मैं थोड़ा बहुत गुनगुना भी लेती थी, तो मुझे याद है कि जब हमारी फेयरवेल पार्टी हुई थी तो उसमें मुझे एक टैगलाइन मिली थी -

बनना है तुझको क्या, सबको दे बता,

कभी तू पी.टी. उषा लगे, कभी लगे लता ।

मुझे क्या पता था कि इस राजनीति के मैदान में यहां पर आकर हमें खेल करना पड़ेगा । जब से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, उनके खुद का बहुत ज्यादा रूझान खेलों की तरफ है । इसलिए आप देखिए कि सरकार की तरफ से कितनी योजनाएं हैं । चाहे हम 'फिट इंडिया मूवमेंट' की बात करें तो उसके अन्दर चार मुख्य बातें सरकार की तरफ से रखी गई । सबसे पहले साल में फिजीकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया गया । इसके बाद दूसरे साल में डायटरी हैबिट्स की तरफ ध्यान दिया गया कि आपका खान-पान किस तरह का होना चाहिए । तीसरे साल के अन्दर इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल के बारे में कहा गया । आपने देखा होगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कॉप-27 के अन्दर भी LiFE – Lifestyle for Environment, इस पर उन्होंने खासकर फोकस किया । इसके साथ-साथ चौथे साल में डिजीज प्रिवेंशन को तवज्जो दी गई है । सभापति महोदया, 'खेलो इंडिया' के तहत पिछले दिनों पंचकुला में जो यूथ गेम्स हुए, वहां

माननीय मंत्री जी गए थे और मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो लोकल गेम्स हैं, उन्हें हमारी सरकार किस तरह से बढ़ावा दे रही है। आप देखेंगे कि जो मल्लखम्भ है, जिसके बारे में महाराष्ट्र के हमारे आदरणीय सांसद बात कर रहे थे, मैंने खुद देखा कि बच्चे कमाल करते हैं। एक नन्हा-सा बच्चा, छ:-सात साल का, जिस तरह से वह मल्लखम्भ की प्रैक्टिस करके दिखा रहा था, वह अद्भुत था। इसके साथ-साथ अगर आप योगा की बात करें और गतका, कलेरिपट्टु, थंगटा, ये सब पाँच गेम्स को इसके अन्दर इन्क्लूड किया गया है।

अभी पिछले दिनों गुजरात में जो खेल सम्पन्न हुए, आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरा गुजरात खेलमय हो गया था। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे Centre of Excellence Scheme है, Come and Play Scheme है। इसके साथ-साथ National Sports Talent Contest Scheme और Special Area Games Scheme है। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाह रही थी कि हमारी जो बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं, चाहे हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, चाहे टोक्यो ओलम्पिक की बात करें, लेकिन हम फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें और अच्छा कर सकते हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसको और ज्यादा बढ़ावा दें।

माननीय सभापति महोदया, अगर मैं खासकर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वे लड़के हैं, चाहे लड़कियां हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। वहां के माननीय मुख्य मंत्री जी वहां के हमारे खिलाड़ियों को करोड़ों में रुपये देते हैं। इसके साथ-साथ हरियाणा सरकार ने यह किया है कि अगर कोई भी गांव, कोई भी पंचायत ढाई एकड़ की जमीन देता है तो वहां पर सरकार की तरफ से खेल स्टेडियम बनाए जाते हैं, ताकि बच्चों का ध्यान खेलों की तरफ ज्यादा जा सके।

यहां पर हमारे दोनों माननीय मंत्री जी बैठे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे एरिया के अन्दर, मैं थोड़ा-सा अपने एरिया की भी बात करूं तो मेरा सिरसा लोक सभा संसदीय क्षेत्र बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर है और पंजाब की वज़ह से वहां के हमारे युवाओं में नशे का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। माननीय मंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर सिरसा के अन्दर, फतेहाबाद के अन्दर सिंथेटिक एथेलेटिक्स ट्रैक, हाई-मास्ट लाइट्स के साथ लगाए जाएं तो वहां के युवाओं का खेलों के अन्दर बहुत अच्छा प्रोत्साहन होगा।

नरवाना में एक नवदीप स्टेडियम है। अगर वहां पर भी सिंथेटिक एथेलेटिक्स ट्रैक बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि वहां के बच्चों को भी इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके साथ-साथ एक हाई-टेक जिम और हाई-टेक स्पोर्ट्स होस्टल की भी सिरसा और फतेहाबाद के अन्दर बहुत बड़ी जरूरत है।

अगर हम रानी रामपाल की बात करें, जो हमारी पिछली बार की हॉकी टीम की कैप्टन थी, और इस बार जो सविता पुनिया, गोलकीपर और कैप्टेन है, वे हमारी सिरसा लोक सभा क्षेत्र से ही आती हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ कर यह विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप मेरे सिरसा लोक सभा क्षेत्र की तरफ ध्यान देंगे तो वहां के जो बच्चे नशे की तरफ धीरे-धीरे जा रहे हैं, हमारी यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह से यूथ्स को नशे से निकाल कर खेलों की तरफ ले जाएं। मेरा इनसे नम्र निवेदन है कि अगर वे वहां पर स्पोर्ट्स का कुछ एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी काम करेंगे तो वहां के बच्चों को इसका बहुत लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे हरियाणा के अंदर बेटियों के बारे में कहा जाता था कि उनको यहाँ कोई सम्मान नहीं दिया जाता है और यहाँ पर फीमेल फीटिसाइड है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब पानीपत की धरती पर आए थे तो उन्होंने 'बेटी पढ़ाओ – बेटी बचाओ' का नारा दिया था। उसके बाद आपने महसूस किया होगा कि रेशियो के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आया है।

इसके साथ ही मैं फोगाट सिस्टर्स के पिताजी को बहुत-बहुत धन्यावाद करना चाहती हूँ। उनके सिर्फ तीन बेटियाँ ही हैं। उन्होंने अपने बेटियों का पालन-पोषण बेटों से भी बढ़ कर किया है। जब वह उनको खेल के अंदर लेकर गए तो आपने देखा होगा कि एक के बाद एक सारी फोगाट सिस्टर्स इनामात लेकर आयी हैं। हमारे मन के अंदर एक भाव है कि बेटा वंश को आगे बढ़ाता है और बेटियाँ बिल्कुल ही किसी काम की नहीं होती हैं। इस प्रकार लोगों के मन के अंदर जो भाव है, वह आज खत्म हुआ है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे खेलते हैं, अगर वह जीत नहीं पाते हैं तो आप देखिए कि एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। जो हार जाते हैं, उन बच्चों को भी अपने मन में किसी तरह का मलाल नहीं रखना चाहिए। अगर वह लगातार अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर एक दिन जीतेंगे, क्योंकि:

गिरते हैं शहसवार ही मैदान-ए-जंग में,

वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले।

महोदया, बहुत -बहुत धन्यवाद।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you Madam Chairperson for giving me the opportunity to speak in an important discussion on the sports development in India.

Hon. Chairperson, in the year 2022 and over the past few years also, India has seen a splendid performance from our athletes at many events at the global level. Recently also, in the Commonwealth Games 2022, we have seen a total medal tally of 61 -- 22 golds, 16 silver and 23 bronze -- which is one of the best performances India has ever seen in such tournaments. Also, I would like to congratulate all our sportspersons who have displayed exemplary athleticism at a world class level.

When we look at these glorious moments or when we look at these athletes, it is not just that we look at this one moment or that one athlete performing at that one event, but we also have to remind ourselves that such events are a culmination of decades of investment in infrastructure and also in sporting talents. In our country, it is quite natural when the urgent priorities are welfare, health, education, social security, development of logistical infrastructure like roads and public transport, the sports infrastructure or the sports spending always does not meet the demand that it needs to be met. So, the Government has to look at alternative funding models or creative or innovative spending in the sporting system.

One suggestion that I would like to make is this. I have with me the figures of a national CSR portal run by the Ministry of Corporate Affairs. Approximately, Rs.24,864 crore had been spent on CSR in 2020-2021. Out of this, if you look at the sports spending, it is just Rs.240 crore. So, this CSR spending can be improved, if, within the CSR portal, the State Governments and the Central Government can list out the priority spending areas in sports.

The other Members, who have spoken before me, also mentioned that it is not just about constructing these large stadiums worth hundreds and thousands of crores but we have to look at the spending at the grass-roots level which is at the schools and colleges. There are excellent grounds but in reality, right now, if we look at these grounds at the village level, they are used for grazing cattle.

These are the first grounds that any kid is introduced to, and these should be the nurturing places for all these sporting talents. But that minimum infrastructure has to be provided. So, instead of just looking at spending a high amount of budget on these big stadiums, we have to look at the expenditure that we make in the rural areas also.

I will appreciate the Khelo India Scheme which is a very good scheme. It is penetrating very well at the district level. But why do we not take a step forward and go to the schools also? Let us identify those schools with good grounds. Why do we not improve the infrastructure there? That is one of the suggestions.

Also, regarding alternative career paths, when many of the sporting talents come to the college level, they see playing as an athlete or being a sportsperson might not be a career for them. So, they divert themselves into other academics or they stop playing sports completely. Which is why, though some might be passionate being in the sports arena, they may not play. Or, some are injured players who still want to be associated with the sports. So, the Government should also encourage other sporting career paths such as data analytics in sports, nutritionists, fitness experts. Like this, it should encourage something which can improve their career.

Madam, please give me one minute more, and I will conclude.

One more important thing which others have also mentioned is, why we do not promote our traditional sports. With westernization of our culture, we have imported a lot of sports from other countries, and we are only concentrating on them. But there are a lot of sports like kushti, kabaddi, mallakhamb, which is even referred to in Ramayana also, kho-kho, gilli danda, lingocha, vallam kali, etc. There are very many sports, and these are just small examples of the numerous sports which are played at rural level or village level. The Government has to concentrate on improving and encouraging these sports.

One more point that I wanted to mention is that Pitta Bhagya Chandra Yadav from my constituency went to Nepal in Karra Samu, which is Silambam, which is a very local sport played in festive seasons. It has got him international recognition, and we all feel proud for it. So, there is a lot of scope in traditional sports also.

The other thing that I want to talk about is the National Sports University in Manipal.

माननीय सभापति: खेल से क्या लाभ है, क्या मिलता है, इस पर प्रकाश डालना चाहिए। पूरी दुनिया खेल रही है।

....(Interruptions)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Last minute, and I am concluding. ....(Interruptions) There is a National Sports University in Manipal. There can be a university specifically for water sports. I would like to invite the Central Government to invest in Andhra Pradesh for this. We have about thousand kilometers of coastline. It is a good destination for improving water sports.

Madam, I come from a district, from where hails Karnam Malleswari, the first Indian woman who has won an Olympic medal in Sydney Olympic in 2000. I would like the Central Government to invest more in Khelo India in our district of Srikakulam. ....(Interruptions)

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदया, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर दोनों अभी यंग हैं। यकीनन हमारी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। मोरक्को बहुत छोटा सा देश है, लेकिन जब उसने ब्राजील को हराया तो शायद ब्राजील ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोरक्को से हम हार जाएंगे। मेसी की अर्जेंटीना को जब सऊदी अरब ने हराया तो अर्जेंटीना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सऊदी अरब हमें इस तरह से हरा सकता है। ये दोनों टीम्स, चाहे मोरक्को हो या सऊदी अरब, पिछले पांच सालों से यह सोचकर लगातार मेहनत कर रही हैं कि हम उतरेंगे तो जीतेंगे। 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश के अंदर हम लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? हम टेलीविजन के सामने बैठे हुए थे और हम ताली बजा रहे थे। खिलाड़ी कोई और था मैदान के अंदर, लेकिन हम खुश हो रहे थे कि कितना अच्छा गेम हो रहा है। हमें अफसोस इस बात का होना चाहिए कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हमने 11 फुटबाल खिलाड़ियों को तैयार नहीं किया। उस दिन सारे देश ने इस बात का चिंतन किया और यकीनन आपने भी सोचा होगा कि कहीं न कहीं हमारी खेल नीतियों के अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, वरना 135 करोड़ देश की आबादी में अगर हम एक टीम तैयार नहीं कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ, कहीं न कहीं गलत हो रहा है। इस बात का एहसास हुआ है और शायद उसी एहसास को लेकर आज हम सभी लोग यहां इकट्ठा हुए हैं।

मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूएस और चाइना ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनके खिलाड़ी मैदान के अंदर उतरते हैं, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जब आर्गनाइज होता है, तो उनके खिलाड़ी गोल्ड ऐसे ही हंसते-हंसते लेकर चले जाते हैं। हम अगर एक गोल्ड लेकर आ जाते हैं तो पूरा देश सेलीब्रेट करता है। बल्कि प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए, पूरे मिनिस्टर्स ले लीजिए, सभी चीफ

मिनस्टिर्स उसका जश्न मनाते हैं। हमारे पास पोटेंशियल इससे ज्यादा है। कहीं न कहीं हम कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जो वे कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? वे बचपन से ही अपने खिलाड़ियों को आइडेंटीफाई कर रहे हैं। हमारा कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल के अंदर है और उसके बाद की पूरी जिम्मेदारी उनके स्पोर्ट्स एसोसिएशन, फेडरेशंस और वहां की सरकार उठा रही है।

मंत्री जी, हमारे शार्ट टर्म गोल्स और लांग टर्म टार्गेट्स क्या होने चाहिए, इसको आइडेंटीफाई करने की जरूरत है। मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर एक सर्वे करवाइएगा कि कितने ऐसे स्कूल्स हैं कि जहां पर स्पोर्ट्स टीचर्स मौजूद हैं। पूरे देश के अंदर, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों या गवर्नमेंट स्कूल्स हों, स्पोर्ट्स टीचर्स कितने स्कूल्स के अंदर हैं? एक सर्वे करवाइगा कि कितने स्कूल्स के अंदर प्ले ग्राउंड्स मौजूद हैं? एक सर्वे करवाइएगा कि अगर ग्राउंड मौजूद है तो स्कूल के अंदर क्या एक फुटबाल है, एक क्रिकेट की किट है, एक रेसलिंग की मैट है और क्या वहां पर बास्केटबॉल के लिए कोई सुविधा है? पूरे देश के प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स में एक सर्वे करवा लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग अगर खेलों के अंदर पीछे हैं, तो इसकी वजह क्या है?

सभापति महोदया, मैं आपके जरिए मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि 75 वर्ष देश की आजादी के हो गए हैं, हम वैसे भी करोड़ों रुपये ऐसे-वैसे कामों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। मंत्री जी, यह जिम्मा उठाइएगा कि 75 साल देश की आजादी के मौके पर हम हर स्कूल को एक स्पोर्ट्स किट प्रोवाइड करेंगे, इसमें एक फुटबॉल रहेगा, एक रेसलिंग का मैट रहेगा, बैडमिंटन और वॉलीबॉल के लिए जो नेट लगेगा, वह भी रहेगा। मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूं, उसके ऊपर लिखिएगा कि अगर खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। उसके ऊपर आप अपनी तस्वीर लगाइए, पंत प्रधान जी की भी तस्वीर लगाइए।

इसे 75 वर्ष का तोहफा बोलकर देश के तमाम स्कूल को दीजिएगा। हर राज्य के अंदर कम से कम चार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मेरे शहर के अंदर थी, लेकिन पुणे वाले ने उसे उठाकर पुणे लेकर चले गए। हम जमीन ढूंढते रह गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पुणे लेकर चले जाएंगे। चार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, जिसका फोकस स्पोर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स रिसर्च और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन होना चाहिए।

मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि औरंगाबाद के अंदर एक साई का एक एक्सिलेंसी सेंटर है। आज तक आपने इसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, लेकिन वहां पर कोई भी इंटरनेशनल लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। खेलो इंडिया के जरिए अंडर-17 टैलेंट को आप आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को यह जिम्मेदारी दीजिए कि अंडर-14 के जितने भी टैलेंट है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए।

भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी बृज भूषण सिंह जी हैं, जो खुद एक पहलवान हैं। अगर वह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिसने कभी जिन्दगी में गोल नहीं किया, वह फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो जाता है, जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ी, वह क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो गया है।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप एक नियम बनाइए और राजनेताओं को खेलों से दूर रखिए, तभी हमारे खिलाड़ी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी बहुत सारा डिस्कशन खेलों के ऊपर हुआ। यकीनी तौर पर खेलों की वजह से मेंटल और फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होती है, जिससे देश की हेल्थ एक्सलेंट हो जाती है।

मैं मंत्री जी का ध्यान शूटिंग के लिए आकर्षित कराना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर शूटिंग के लिए बहुत पोटेन्शियल है। मैं मुरादाबाद शहर से आता हूं, वहां करीब डेढ़ सौ बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, लेकिन फेसिलिटीज कुछ नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शूटिंग रेंज हर जगह बननी चाहिए। मुरादाबाद में अब से 60 साल पहले शूटिंग रेंज हुआ करती थी, अब उस पर कॉलोनीज डेवलप हो गई है। पैसे की कमी की वजह से बच्चों को इनकरेज नहीं कर पाते, बच्चे प्रैक्टिस के लिए मेरठ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं।

मैं मंत्री जी के संज्ञान में बहुत महत्वेपूर्ण बात लाना चाहता हूं, हर जिले में राइफल क्लब मौजूद है, उस राइफल क्लब के लाइसेंस का रिन्यूएल होता है, उस रिन्यूएल के लिए फीस ली जाती है, राइफल क्लब की फीस अलग से ली जाती है।

मंत्री जी, राइफल क्लब की फीस कहां जाती है, वह राइफल क्लब पर नहीं लगती है। अगर आप उसका ऑडिट करा लें कि हर जिले में राइफल क्लब के रिन्यूएल के लिए जो पैसा लिया गया है, वह पैसा इस पर खर्च हुआ या नहीं। इससे राइफल क्लब को भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और आपको फंड देने की जरूरत नहीं है। वह अपने आप डेवलप हो जाएगी।

मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मुरादाबाद में इंटरनेशनल लेवल की अच्छी शूटिंग रेंज बने। मुरादाबाद में 150 बच्चे नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, वहां पर शूटिंग रेंज बनवाई जाए ताकि ये बच्चे देश का नाम रोशन कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं पहले खेल मंत्री अनुराग जी और सहयोगी निशीथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक कहावत है, कुछ भी आगे बढ़े, उसके लिए एक स्लोगन चाहिए। नरेन्द्र मोदी जी ने पब्लिक के सामने खेलो इंडिया का संकल्प दिया, यह संकल्प बहुत बड़ी बात है। इसके साथ-साथ, प्लेयर्स को सहयोग करने के लिए assistance to national sports federation का काम किया, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दे रहे हैं, pension to meritorious sportspersons को दे रहे हैं। Pandit Deen Dayal Upadhyay National Welfare Fund for Sportspersons को दे रहे हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड दे रहे हैं।

पहली बार इंडियन ओलपिंक्स में पी.टी. उषा जी को सम्मान दिया। आप आंकड़े देखिए, ओलंपिक्स गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में हम थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। हां, हम मानते हैं कि एक दिन में सब कुछ नहीं होगा। एक बात सही है, माननीय प्रधान मंत्री जी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग जी की सोच आगे बढ़ने की है। मेरे कुछ सुझाव आगे बढ़ने के लिए हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया डायरेक्टली कुछ नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मदद जाती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज युवा क्रीड़ा के आफिस होते हैं, युवा क्रीड़ा के ऑफिस का क्या काम है, हम कुछ नहीं जानते हैं। मैंने देखा है, वैस्ट बंगाल में एक कोच भी है। निशीथ जी ने स्टेडियम के लिए सैंट्रल गवर्नमेंट को तैयार किया, फंड भी दिया लेकिन जमीन नहीं मिली। 500 करोड़ रुपये फिर से बैक लाने की कोशिश है, रेल मंत्रालय ने जमीन दे दी है।

महोदया, स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया, साई के अंतर्गत पंचायत लैवल पर तो नहीं कर पाएंगे लेकिन ब्लॉक और सब डिवीजन लैवल पर ट्रेनिंग कैम्प रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम कहते हैं कि एससी, एसटी के लिए काम करेंगे। हम हर जगह चुनाव करते हैं तो पापुलेशन कैलकुलेट करते हैं, मैं अनुराग जी से कहना चाहता हूं कि कितने प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, इनकी काउंटिंग होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लैवल पर अफसर कम से कम नाम लिखकर रखें कि कौन माध्यमिक लैवल पर अच्छा है और कौन कॉलेज लैवल पर अच्छा है। जब हम चुनाव नहीं करेंगे, आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। जैसे फुटबाल में कल्यान चौबे को सम्मान दिया है, अच्छा किया है, पी.टी. उषा को सम्मान दिया है, अच्छा किया है। ऐसे ही कबड्डी, लांग जम्प, हाई जम्प और अन्य खेलों को साथ में लेकर आगे जाना है, इसके लिए आपको गांवों की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमने साई के स्टेडियम देखे हैं, सिर्फ सहरांचल में देख रहा हूं। मेरी विनती है कि विष्णुपुर सब डिवीजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन को कम से कम मदद करनी चाहिए। आप सब डिवीजन में मदद करेंगे, उतना अच्छा होगा।

मैं अनुराग जी को महिला क्रिकेट टीम के लिए बधाई देता हूं। मैं कार्तिक चिदम्बरम जी की बात सुन रहा था, वह कह रहे थे कि कुछ नहीं किया। मैं बोल रहा हूं कि पहली बार महिला क्रिकेट को भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना पुरुष टीम को मिलता है। इसे बराबर कर दिया है।

महोदया, विष्णुपुर में एरोड्रम है जो ब्रिटिश के समय से है। मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि यहां स्टेडियम बनाया जाए। अग्निवीर के जितने लड़के आएंगे, हमारे यहां से जो भी स्पोर्ट्स में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरी यही विनती है कि हमारे यहां भी स्टेडियम बना दीजिए। सब आगे बढ़ें, खेलो इंडिया, हम सब खेलेंगे।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति जी, नियम 193 के तहत खेलों और खेल की सुविधा पर चर्चा हो रही है। 132 करोड़ की जनसंख्या का देश है। अगर खेलों में मेडल की बात करें, अमेरिका हो या चीन हो, अन्य देशों की तुलना में खेल में मेडलों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। माननीय मंत्री अनुराग जी का खेलों के प्रति लगाव है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब से माननीय मोदी जी की सरकार देश में आई है, निश्चित रूप से पिछले पांच-छः सालों से खेलों के प्रति देश में अच्छा काम हो रहा है।

लेकिन, अब भी ग्रामीण इलाकों में जितनी सुविधा शहरों में मिलती है, चाहे वह स्टेडियम की सुविधा हो या अन्य सुविधा हो, उतनी सुविधा ग्रामीण इलाकों में नहीं मिलती है। ग्रामीण इलाकों में भी कई अच्छे खिलाड़ी हैं। स्कूल में खेल खेलने वाले या स्कूल से आगे तक जाने वाले कई अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर उनको सुविधा मिलेगी तो निश्चित रूप से वे भी इस देश का नाम रोशन करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो खिलाड़ी ओलम्पिक खेल में या अन्य स्पर्धा में मेडल लेकर आते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा उन खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये बख्शीश के रूप में दी जाती है। अगर वही पैसा अच्छे खिलाड़ियों पर लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम होगा। महोदया, मैं जिस क्षेत्र से, जिस राज्य से आता हूं, उसका जिक्र माननीय श्रीनिवास पाटिल जी ने किया है। कुश्ती के क्षेत्र में इस देश को ओलम्पिक का पहला मेडल खाशाबा जाधव जी ने दिलाया था। उनके परिवार ने उनके नाम पर पद्मश्री देने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया था। राज्य सरकार ने तो सिफारिश की थी। लेकिन, आज तक उनके परिवार को पद्मश्री के बारे में केंद्र सरकार द्वारा राहत नहीं मिली है। मैं इस चर्चा के दौरान इस विषय को भी उठाता हूं।

दूसरा, सीएसआर फंड के द्वारा कई कंपनियां, जैसे महाराष्ट्र में कई सारी कंपनियां अपना सीएसआर फंड अन्य राज्यों को देती हैं। ये कंपनियां 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा सीएसआर फंड इस देश में यूज करती हैं। अगर इस सीएसआर फंड का उपयोग ज्यादा से ज्यादा खेल के मैदान के लिए या खेल की अन्य सुविधा के लिए किया जाए तो निश्चित रूप से खेल को फायदा होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि खेलों की कई सारी सुविधाएं राज्य सरकार या स्थानीय नगर निगम देती है, अगर केंद्र सरकार द्वारा हर राज्यों को सूचित किया जाए कि खेलों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च और खेलों की सुविधा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम होगा। जैसे रेल विभाग द्वारा कई खिलाड़ियों को नौकरी दी जाती है। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा भी नौकरियों का आश्वासन दिया जाएगा तो निश्चित रूप से अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। महोदया, देश में अच्छी गुणवत्ता वाले खेल में बुनियादी ढांचे की कमी है। हमें यह भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हर खेल में अच्छे-अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर उनको केंद्र सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाएगी तो आने वाले दिनों में ओलम्पिक गेम में, एशियन गेम में या अन्य किसी भी गेम में इस देश का नाम निश्चित रूप से रोशन करेंगे।

इस चर्चा के दौरान सभी माननीय सदस्यों ने जो-जो मुद्दे उठाये हैं, वह केवल चर्चा न रह जाए, बल्कि उस पर कार्रवाई भी हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Madam, today morning, I happened to see a Facebook post by a former media reporter on sports development in India. The crux of the post is simple. While countries across the world are investing in building sports infrastructure for promoting young talents, in India, we are spending money on building tall and wide statues.

Madam, for the World Cup Football 2022, Qatar has spent USD 6.50 billion for building eight stadiums. In anticipation of hosting the 2030 World Cup, Morocco is building a stadium with a capacity of 93000 people in Casablanca. During this discussion, I have to reveal some bitter truths in this august House. In India, we spent Rs. 2,930 crore for Statue of Unity, spending Rs. 2,500 crore for Ram Statue in Ayodhya, and Rs. 1,000 crore for Statue of Equality, and the list goes on.

Madam, this Facebook post reflects the state of sports development in India. Every time a Football World Cup or Olympics gets concluded, and our Governments and sport administrators dream of getting a berth in the next World Cup for increasing the medal tally. But after a few days, we would be back to square-one and will think of it only after four years. I still remember, long back, a former Union Sports Minister had claimed that in the next Olympics, India would win 100 gold medals.

Luckily, we got at least one gold medal in athletics in the Tokyo Olympics last year after waiting for 100 years. We only know how to make tall claims, but lack the political will to implement those claims. We will soon become the most populated country in the world bypassing China. But where do we stand in terms of sports development? Are we having a national programme for promotion of sports other than Khelo India? The answer to it is definitely 'No'.

The slogans like Beti Bachao Beti Padhao are not enough for promotion of sports. This Government has shown keen interest in encroaching on the rights of States in matters like agriculture and cooperation, though they are included in the State List in the Seventh Schedule to the Constitution.

If the Government had shown at least a fraction of this interest in sports -- which also is a subject in the State List – then the fate of sports in the country would have been much better. Unfortunately, this Government has left it entirely to the States and washed off its hands without providing sufficient funds for the States.

Youth are the major assets of our country and if their energy is not channelized properly, then naturally they will be diverted to undesired paths. The anti-national elements are pouring-in tonnes of drugs and other narcotic substances to trap our youth that is seriously affecting their future whereas this Government remains a mute spectator. Our discussion would be fruitful only if the Government shows the political will to curb the menace of drugs and channelize the energies of our youth towards sports.

We need a good sports policy. We need playgrounds for our children in every village and small stadiums in every local body, and for that the need of the hour is allocation of sufficient funds to the States and local bodies.

I request the Government to make a masterplan to develop sports infrastructure across the country so that our young talents could be nurtured to their best possible extent. Thank you.

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी) : महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया । हमारे दोनों मंत्री जी माशाल्लाह जवान हैं, एनर्जीटिक हैं । मैं अनुराग भाई को तो कई सालों से जानता हूं । मैं मुंह पर तारीफ नहीं कर रहा हूं, कल को हमारे ही लोग कहेंगे के ये बीजेपी की तारीफ करते हैं । जब कोई आदमी अच्छा काम करता है, तो तारीफ करते हैं, अगर कोई नहीं करता है, तो तारीफ नहीं करते हैं । जैसे आप लोगों ने आज गुजरात में किया है । आपने एकदम ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी । वह रिकॉर्ड में है ।

मेरा यह कहना है, जैसे आप जवान हैं, आप लोगों ने गांवों में टैलेंट ढूंढ़ना शुरू किया है । मैं अफ़सोस के साथ यह कहना चाहूंगा कि हर जगह पॉलिटिक्स आ जाती है । जो आपके इलाकों में काम कर रहे हैं, मैं आपसे यह कहूंगा, आप मालूम कीजिए कि टैलेंट ढूंढ़ते वक्त वह देखते हैं कि वह हमारी पार्टी का बच्चा है या नहीं । यह नहीं होना चाहिए । जो भी टैलेंटेड है, उसको उभारना चाहिए । आप उसकी हिम्मत अफ़ज़ाई कीजिए । हमारे एक भाई ने अभी कहा, जब कोई ओलंपिक जीतकर आता है, तो आप लोग उसको गोल्ड मेडल देते हैं । उनको बड़े-बड़े ईनाम देते हैं । मिनिस्टर्स एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत करते हैं । गांव के जो बच्चे ऊपर उठ रहे हैं, हर स्टेज पर उनका उत्साहवर्धन किया जाए । उनके घरों की हालत ये है कि वे रोज़ाना एक गिलास दूध नहीं पी पाते हैं । वे बच्चे आगे चलकर क्या खेलेंगे? उनकी गरीबी का कुछ इंतज़ाम किया जाए । उनके घरों में लाइट नहीं है । आप उनके पढ़ने के लिए क्या इंतज़ाम करेंगे?

महोदया, जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये बच्चे वे नहीं कर पाते हैं, जो दूसरे करते हैं । आप इसका शुरू से ख्याल कीजिए । एक अफ़सोस की बात और है कि हर चीज में पॉलिटिक्स आ जाता है । सेलेक्शन में पॉलिटिक्स आता है । सेलेक्शन में अच्छे-अच्छे बच्चे रह जाते हैं । पॉलिटिक्स का असर उनके ऊपर पड़ता है । जिसको पॉलिटिक्स का सपोर्ट मिलता है, वह आगे चला जाता है । चूंकि वह मैदान में नहीं होता है, इसलिए वह वहां जाकर हार जाता है ।...(व्यवधान) इसी तरीके से जब बच्चियां खेलने के लिए जाती हैं, आप जानते हैं, उनके साथ सेक्स एक्सप्लोइटेशन का मसला है । यह पूरे संसार में है । खासकर इसका ख्याल रखिए । उसके ऊपर पाबंदी लगाएं । बच्चियों को हिम्मत दीजिए, उनको उन बुराइयों से बचाइए ।...(व्यवधान)

جناب بدرالدین اجمل (دھبری): جناب چیرمین صاحب، آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئےمیں آپ کا شکرگزار ہوں۔

جناب، ہمارے دونوں منتری ما شا اللہ جوان ہیں، اینرجیٹِک ہیں، میں انوراگ بھائی کو تو کئی سالوں سے جانتا ہوں۔ میں مُنہہ پر تعریف نہیں کر رہا ہوں، کل کو ہمارے ہی لوگ کہیں گے کہ یہ بی۔جے۔پی۔ کی تعریف کرتے ہیں۔ جب کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو تعریف کرتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو تعریف نہیں کرتے ہیں۔ ۔ جیسے آپ لوگوں نے آج گجرات میں کیا ہے۔ آپ نے ایک دم اولمپِک کا ریکارڈ توڑ دیا ، اس کی تعریف تو کرنی ہی پڑے گی وہ ریکارڈ میں ہے۔

میرا یہ کہنا ہے کہ جیسے آپ جوان ہیں، آپ لوگوں نے گاؤوں میں ٹیلینٹ ڈھونڈنا شروع کیا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر جگہ سیاست آجاتی ہے۔ جو آپ کے علاقوں میں کام کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ معلوم کیجیئے کہ ٹیلینٹ ڈھونڈتے وقت وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پارٹی کا بچہ ہے یا نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہئیے۔ جو بھی ٹیلینٹڈ ہے اس کو اُبھارنا چاہئیے۔ آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجیئے۔ ہمارے ایک بھائی نے ابھی کہا جب کوئی اولمپِک جیت کر آتا ہے، تو آپ لوگ اس کو گولڈ میڈل دیتے ہیں۔ انکو بڑے بڑے انعام دیتے ہیں۔ منسٹرس ائرپورٹ پر جا کر انکا خیر مقدم کرتے ہیں۔ گاؤں کے جو بچے اوپر اُٹھ رہے ہیں، ہر اسٹیج پر انکی حوصلہ افزائی کی جانی چاہئیے۔ ان کے گھروں کی حالت یہ ہے کہ وہ روزانہ ایک گلاس دودھ نہیں پی پاتے ہیں۔ وہ بچے آگے چل کر کیا کھیلیں گے؟ ان کی غریبی کا کچھ انتظام کیا جائے۔ ان کے گھروں میں لائٹ نہیں ہے۔ آپ ان کے پڑھنے کے کیا انتظام کریں گے؟

چیرمین صاحب، جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، یہ بچے وہ نہیں کر پاتے ہیں، جو دوسرے کرتے ہیں۔ آپ اس کا شروع سے خیال کیجیئے۔ ایک افسوس کی بات اور ہے کہ ہر چیز میں سیاست آجاتی ہے۔ سیلیکشن میں اچھے اچھےبچے رہ جاتے ہیں۔ پولیٹِکس کا اثر ان کے اوپر پڑتا ہے۔ جس کو پولیٹکس کا سپورٹ ملتا ہے، وہ آگے چلا جاتا ہے۔ چونکہ وہ میدان میں نہیں ہوتا ہے، اس لئے وہ وہاں جا کر ہار جاتا ہے۔ (مداخلت) اسی طریقے سے جب بچیاں کھیلنے جاتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ سیکس ایکسپلوئی ٹیشن کا مسئلہ ہے۔ یہ پوری دنیا میں ہے۔ خاص کر اس کا خیال رکھیئے۔ اس کے اوپر پابندی لگائیے۔ بچیوں کو ہمّت دیجیئے، ان کو ان بُرائیوں سے بچائیے (مداخلت)۔

(ختم شد)

18.00 hrs

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE(RAIGAD): Hon'ble Madam Chairperson, thank you very much for giving me this opportunity to participate in this discussion on sports under Rule 193. All the hon. Members of this House have expressed their feelings in this regard … (Interruptions)

माननीय सभापति: आपने मराठी में बोलने के लिए नोटिस नहीं दिया है। आप हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में बोल लीजिए।

… (व्यवधान)

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे : मैंने आपको शुरू में नोटिस दे दिया था।

माननीय सभापति: नहीं, हमारे पास नहीं आया है। आप अंग्रेजी में बोल लीजिए।

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE: Madam, when I gave my letter, it was mentioned in it that I was going to speak in Marathi. It is written in the letter. Please see that. I cannot speak because it is already 6 o'clock now.

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप कल बोल लीजिएगा। प्लीज, कल बोल लीजिएगा।

… (व्यवधान)

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे: निशिकांत जी, आप मैडम से मुझे दो मिनट देने के लिए बोलिए। अभी यहां पर आप हैं, अनुराग जी हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप कल अच्छे से बोल लीजिएगा।

SHRI S. GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI): I would like to express my view on Discussion Under 193 of the need to promote sports in India and steps taken by the Government.

In a fast-developing country like India, there is a dire need to encourage non-traditional businesses which have a great potential to flourish and contribute to the country's GDP. Contrary to popular belief, such sectors don't receive the much-needed opportunity which they deserve in order to develop and grow into a full-fledged industry.

As we move into the futuristic age, the Indian government should be on the forefront to create a healthy environment for such businesses to thrive. Sports, a massive and potentially profitable sector deserves the space and support from the government just like any other traditional industry.

In a fast-growing economy like India, there is a tremendous potential for the sports sector to develop and achieve the status of an industry. Previously, the sports sector was considered a loss-making venture but with the boom of multi-sporting events and leagues that is soon to change. India, now hosts the Indian Premier League (cricket), Hockey India League, Indian Super League (football), Pro Kabbadi League and Indian Badminton League, all of which have aided in the growth of the sports sector.

As the sporting scenario in India is evolving, we are witnessing an ever-growing demand for sports entrepreneurship. This is the right moment to venture into the sports sector, where there is ample room to flourish. We, as a country, must award sports an industry status, given the fact that, now, India is not just recognised through cricket but also through other sports such as tennis, badminton, hockey, athletics and much more.

Once, sports is recognised as an industry, it can generate a large number of employment opportunities in the form of the apparel and equipment sector, sports medicine, sports tourism and other sport-related sectors.

As the sports sector is well on its path to attain industry status, there has been a sudden demand for industry-based sports education programmes. We see a spurt in sport management programmes, sports medicines, sports tourism and affiliated sectors.

This is a sign for the Indian government to take effective methods to promote programmes that cater to the industry-based sports education.

In order to attract young and visionary entrepreneurs to the sports sector, the Indian government must increase funding and offer tax holidays for sports-based firms. This move will serve as an impetus in the growth of an industry which has a global presence. India has a great potential for sports entrepreneurship, thanks to the existing huge market but the lack of government initiatives have hindered the growth of this potential sector. We need to create sectors like SEZ for sport-specific companies which will aid the growth of the sports sector.

The Indian government must invest in technological advances such as sports analytics to assist in coaching professional athletes. It must also provide wearables, sensors, and nutrition as per the requirement of the sport and the sportsperson.

Also, the government must invest in professional coaching which will increase the quality guidance give to the Indian sportsperson. There is also a need to bring in performance apparel and equipment of international standard for our athletes. Lastly, partnerships with tech companies and progressive governments will attract the best talent in the sports arena.

A Public-Private Partnership (PPP) model works best for building sports infrastructure. Also, a long-term land lease will help to get adequate land to build such facilities. India being the second most populated country in the world has the ability to churn out athletes who can put us on the global map in terms of sports, other than cricket. We've already seen the rising stars in India putting on splendid performances, but the facilities provided to such brilliant performers are far from good. A perfect blend of private and public partnerships is the solution to the troubles India faces when it comes to providing world-class sports infrastructure to its budding athletes.

India's abysmally poor performance at the Olympics is nothing new. India has consistently failed to foster players with a competitive edge in any sport other than cricket. Even a large amount of public and private investment in sports has failed to produce substantial results.

These failures are often attributed to the model of sports governance in India. Allegations of nepotism, fiefdom, unaccountability and financial irregularities give credence to such views. But in the recent past, it seems, the Indian state has started taking a keen interest in sports. However, it remains to be seen if the increase in the budgetary allocation will galvanise any significant change at the ground level.

Constitutionally, sports form a part of Entry 33 of the State List, under Article 246 of the Seventh Schedule of the Constitution of India. Sports is clubbed together with entertainment, cinematic performances and amusement. There is also no specific enactment for the entire country. Constitutionally, sport is a state subject.

In 2011 the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, notified the National Sports Development Code of India 2011. This code superseded all notifications and instructions by the Government of India pertaining to good governance of the National Sports Federations. What is not certain is whether the National Sports Federations comply with the conditions of the code. Various high courts and the Supreme Court, though, have upheld the binding nature of the provisions of the Code.

The Government of India's attempt to promote sports and fitness has led to many changes, at least at the policy level, in the last five years. These changes also seem to have created duplications in policy; both the SamagraShikshaAbhiyaan and Fit India Movement are called upon to provide sports equipment to government schools and ensure maintenance. This raises questions about whether schools will get funding from both these programmes and about who these schools will be accountable to.

Khelo India Youth Games (KIYG) now seems to have superseded Khelo India School Games (KISG), but what this means has not been clearly articulated. Does it include both schools and universities under one umbrella or will there be one set of Khelo India games for the schools and one set for the universities each year?

It is also unclear what the objective of these programmes is, considering that the experts endowed with the responsibility to conceive, articulate and implement the policy have conflicting views on it.

Some experts advocate inculcating a sports culture minus the competitive aspect, others desire excellence in sports, and then there are also those who want to include traditional and regional sports within the ambit of sports. There also seems to be less clarity on the differences between sports for excellence and sports as a pastime or a hobby or a leisure activity or just for fitness. Then, some have been talking about physical education (PE) being part of the school curriculum.

The Khelo India programme talks about "reviving India's sports culture at the grass-root level by building a strong framework for all sports played in our country and establishing a great sporting nation". The Fit India Movement India as mentions that the schools are also allowed to include their traditional and regional games. Does this mean the schools will have three sets of designated periods during school hours: one for physical education, one for sports that will lead to the participants striving towards fulfilling Khelo India objectives, and one for maintaining fitness that could include traditional and regional games?

At the governance level, corruption, lack of transparency and unclear demarcation of rights and responsibilities have environment of confusion and malpractice. For created an instance, in 2012 the Indian Olympic Association (IOA) was suspended from the International Olympic Committee (IOC) for electing members with pending criminal cases against them in its governing body. This forced Indian athletes to compete at the Sochi Winter Games under the IOC flag, instead of the Indian banner.

There is a need for structural changes. The worst thing today is that federations have power without responsibility. Primarily, this is because we are apathetic to how sports fares. Unless we resolve this apathy, there will be no change. Further, Federations will always exist, but we need to find better people to manage federations. We need a watchdog on federations to ensure they do their job.

Many experts, at both the national and international levels, feel that if India wants to become a sporting nation, the country will have to invest heavily in building a modern infrastructure and a robust grassroots system.

A major part of the allocation was directed at the Union government's current favourite, Khelo India Games, Even the budgetary support for meritorious sportspersons was reduced by almost 40% from the previous financial year. We were still in a business-as-usual mode, blissfully ignorant about the devastation that would soon befall on the world.

Scarce public investible resources have eluded sports (in India). This is further compounded by misallocation, lack of transparency, poor asset management, and an absence of a framework for measuring the impact of public spending. This is unlikely to change, despite the government's best intentions.

Keeping cricket aside, if we look into sports overall, then there has been significant investment particularly in building infrastructure and making it available across India. Karnataka, for instance, has reasonably good infrastructure for track and field (athletics) around 10-14 tracks including synthetic and mud tracks are available and well maintained. Other than this, we also have sports hostels and other provisions by SAI.

All these ensure that we have facilities available for sports for excellence. States like Haryana and Punjab have provisions available for their specialty sports such as wrestling, boxing, etc."

The issue, is not one of infrastructure but that facilities are underutilised. It highlights that importance of promoting local sports interests by pointing to an example in Kenya. "There is a small town called Iten in Kenya. Iten has produced more than 10 world champions in the last couple of decades and almost every middle-distance runner in the world has been to Iten for training at least once in their lifetime. It started back in the early 1990s, with a Kenyan world champion who wanted to start such training in Iten. Initially, they did not begin with big infrastructure or huge equipment, rather their initial focus was on the education of sports focusing on questions like how can you train better? Essentially focusing on the soft part of learning. Even today if you visit Iten you can see the makeshift gym made with pipes, paint boxes, and cement." India needs to place far more emphasis and investment on the learning aspect of sports.

The former president of IOA, admits that the IOA has not done enough for the athletes. But, according to him, the problem goes much deeper than a shortage of cash or organization. He opines that "sport is rarely at the top of anyone's agenda - and that includes athletes and their families. Sport has always taken back seat vis a vis education."

A young professional footballer trying to break into a topflight La Liga football club in Spain. He feels India is one of the biggest sports markets in the world at the moment. He notes, "At the end of the day, investors globally want to see how they can make money out of a certain sport. This finance factor has changed Indian football for the better over the years." He, however, feels a four-month ISL is not really ideal from the perspective of sponsors, investors, and the Indian players. "If you compare it to the Premier League in England or La Liga in Spain, they have a season for almost nine months. Also, the short duration of the league impedes the development of players, they do not get enough time to develop their skills."

Needless to say, the current model of governance of Indian sports clearly lacks accountability and transparency, which that is conducive corruption, threatening a tournament's overall credibility. Even India's most profitable sports league, the IPL, despite being one of the better-managed Indian professional leagues, has been embroiled in controversy in the recent past. Hence, unless mechanisms are brought in place to govern the huge sums of money and the interests of various stakeholders, tournaments will always run the risk of losing credibility, negatively impacting the future of its players and stakeholders.

Having said that, several civil society organisations are now stepping up to the challenge of transforming India into a sporting nation by equipping children at the grassroots level with the means to dream big. By incorporating sports into children's daily lives, they are not only seeking to boost their confidence, self image and personality, but also open the gateway to a possible

career in sports. Thank you.

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Friday,December 9, 2022/Agrahayan 19, 1944 (Saka)